



भारत ने जिम्बाब्वे को 4 विकेट से हराया

रायपुर में खेला गया महिला क्रिकेट टी-20 सीरीज का पहला मैच

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भारतीय महिला क्रिकेट टीम और जिम्बाब्वे महिला क्रिकेट टीम के बीच शुक्रवार को पहला टी20 इंटरनेशनल मैच खेला गया. इस मैच को टीम इंडिया ने चार विकेट से जीत लिया. इस तरह टीम इंडिया ने इस सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की

कप्तान स्मृति मंधाना ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया. जिम्बाब्वे की महिला क्रिकेट टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 114 रन का स्कोर बनाया. टीम की ओर से शॉन मेयर्स ने नाबाद 43 रन, जबकि केलिस ने 42 रन की पारी खेली. इस तरह जिम्बाब्वे ने भारत को कुल 115 रनों का टारगेट दिया।

115 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही. 19 रनों के अंदर भारत के चार

बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. पहले ओवर के बाद भारतीय कप्तान स्मृति मंधाना और अनुष्का दोनों आउट हो गईं. इसके बाद हरमनप्रीत कौर भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई. उसके अगले ओवर में शेफाली भी आउट हो गईं. इस तरह 19 रन के स्कोर पर भारत के चार विकेट गिर गए. इसके बाद दीप्ति शर्मा और डेब्यू कर रहीं निकी प्रसाद के बीच साझेदारी पनपी और दोनों ने हाफ सेंचुरी लगाईं. जिससे भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच सकी. निकी प्रसाद अंत तक टिकी रही।

राजनाथ सिंह के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार

नई दिल्ली। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने शुक्रवार को कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उन आरोपों पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि विपक्ष बांग्लादेश जैसी घटनाओं से प्रेरित होकर देश में अराजकता फैलाकर सत्ता हासिल करना चाहता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए खेड़ा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को सत्ता से जाने का डर सता रहा है। विपक्ष का मकसद चुनाव के जरिए सरकार बदलना है। लोकतंत्र में चुनाव के जरिए सत्ता बदलने की बात को

गलत कैसे ठहराया जा सकता है? इसके साथ ही उन्होंने 1977 में हुए सत्ता परिवर्तन का भी जिक्र किया।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस 'बोट चोर, गद्दी छोड़' अभियान चला रही है। देश में इस मुद्दे पर आवाज उठ रही है और विपक्ष भी साफ कह रहा है कि मौजूदा सरकार को चुनाव में हराकर सत्ता से हटाना है। विपक्ष का इरादा सरकार बदलने का है और इसमें कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि जब विपक्ष खुद अपनी बात खुलकर रख रहा है, तो राजनाथ सिंह को इस तरह के आरोप लगाने की जरूरत क्यों पड़ी?

पवन खेड़ा ने कहा कि



लोकतंत्र में विपक्ष का काम ही सरकार की नीतियों का विरोध करना और चुनाव के जरिए उसे सत्ता से बाहर करने की कोशिश करना है। उन्होंने 1977 का उदाहरण देते हुए पूछा कि क्या उस समय देश में सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ था? खेड़ा के मुताबिक, जब विपक्ष सड़कों पर उतरता है और

कोई आंदोलन खड़ा होता है, तो सरकार बदलने की मांग उठना स्वाभाविक है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सत्ता परिवर्तन का रास्ता चुनाव ही है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर युवाओं के विरोध प्रदर्शनों का इस्तेमाल राजनीतिक अशांति फैलाने के लिए करने का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष भारत में भी बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा करते हुए सत्ता परिवर्तन की कोशिश कर रहा है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिंह ने कहा कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में हुई घटनाएं कई गंभीर सवाल खड़े करती हैं।

चुनावी हलफनामे में झूठी जानकारी देने पर नागरिक दर्ज करा सकते हैं आपराधिक केस

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि निजी नागरिक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत चुनावी हलफनामों में गलत जानकारी देने या महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने पर निर्वाचित उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 195 के तहत लगाया गया प्रतिबंध ऐसे मामलों में शिकायत दर्ज कराने में बाधा नहीं बनेगा। सीआरपीसी की धारा 195 के तहत आपराधिक अदालतें कुछ विशिष्ट अपराधों का सीधे संज्ञान नहीं ले सकतीं, जब तक कि अधिकृत लोकसेवक या संबंधित अदालत की ओर से औपचारिक रूप से लिखित शिकायत दर्ज नहीं

कराई जाती।

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने कहा, "हमारा मानना ​​है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125ए के तहत किए गए अपराध का आरोप लगाने वाली निजी शिकायत को सीआरपीसी की धारा 195 की कठोर शर्तों पर खरा उतरना आवश्यक नहीं है, जैसा कि उच्च न्यायालय ने माना था।" पीठ ने कहा, "यदि किसी निर्वाचित उम्मीदवार को परेशान करने के लिए शिकायत दर्ज कराई जाती है या उसमें निराधार आरोप लगाए जाते हैं,



तो देश के कानून सक्षम मजिस्ट्रेट को प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुरूप उचित आदेश पारित करने के लिए आवश्यक अधिकार और शक्तियां प्रदान करते हैं।" जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125ए ने उम्मीदवारों को दंडित करने का प्रावधान करती है, जो अपने नामांकन पत्रों या चुनावी हलफनामों में गलत जानकारी देते हैं, विवरण छिपाते हैं या अनिवार्य जानकारीयां उपलब्ध कराने में विफल रहते हैं। न्यायालय ने यह फैसला राजकुमार मडकी की अपील का निपटारा करते हुए सुनाया। मडकी ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के सात मार्च, 2025 के फैसले को चुनौती दी थी।

जातिगत भेदभाव के आरोपों पर घिरे आप नेता

अमृतसर। पंजाब में अमृतसर के पायल से आम आदमी पार्टी के विधायक मनविंदर सिंह ग्यासपुरा को श्री अकाल तख्त साहिब ने तनख्वा घोषित कर दिया है। श्री हरिमंदिर साहिब के सेवादारों पर जातिगत भेदभाव के आरोप लगाने और सिख संस्थाओं के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के मामले में शुक्रवार को यह फैसला लिया गया। श्री अकाल तख्त साहिब के सचिवालय में पांच सिंह साहिबानों की बैठक के बाद जारी आदेश में सिख संगत को ग्यासपुरा से मेलजोल न रखने के लिए कहा गया है। श्री अकाल तख्त साहिब के आदेश के मुताबिक, 12 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक और नेता सचिवालय पहुंचे थे। इस दौरान पहले से जारी आदेश के तहत मनविंदर सिंह ग्यासपुरा को सचिवालय में प्रवेश करने से रोक दिया गया था। इसके बाद उन्होंने सेवादारों पर जातिगत भेदभाव के आरोप लगाए। आदेश में कहा गया है कि 16 अक्टूबर को पहुंचे विधायकों के प्रतिनिधिमंडल ने भी माना कि ग्यासपुरा ने जानबूझकर जाति का मुद्दा बनाया, जबकि उस दिन ऐसी कोई बात नहीं हुई थी।

परिसीमन प्रस्तावों पर सर्वदलीय बैठक की मांग की

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चौथा पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने परिसीमन प्रस्तावों को अंतिम रूप देने और संसद में पेश करने से पहले, इन पर चर्चा के लिए तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। शुक्रवार को भेजे गए इस पत्र में, खड़गे ने प्रक्रियात्मक और संवैधानिक चिंताएं जताई हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 13 अगस्त को मानसून सत्र के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद से अब तक 64 दिनों का एक अभूतपूर्व अंतराल हो चुका है, जबकि सत्र का औपचारिक सत्रावसान भी नहीं हुआ है। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि वह आम सहमति के बिना कोई भी बड़ा संवैधानिक संशोधन न थोपे। सद का मानसून सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित (एडजॉर्न साइन डाई) हुए 64 दिन बीत चुके हैं, लेकिन संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान (प्रोग्रेशन) अभी तक नहीं हुआ है।

उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका, आनंद दुबे शिंदे कैप में आए

मुंबई। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना से इस्तीफा देने वाले आनंद दुबे, शुक्रवार को ठाणे में उममुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए। उद्धव ठाकरे गुट के लिए एक बड़े राजनीतिक झटके के रूप में, आनंद दुबे ने इस हफ्ते की शुरुआत में पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। कई सालों तक, वे पार्टी के एक मुखर रक्षक रहे, जिन्होंने स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में पार्टी की नीतियों का बचाव किया। लेकिन अब यह बचाव खत्म हो गया है। भारी मन और दुःख स्वर में, उन्होंने तुरंत पार्टी छोड़ने की घोषणा की- मैं अपनी पार्टी, शिवसेना से इस्तीफा दे रहा हूँ। मैं अपनी प्राथमिक सदस्यता और राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद, दोनों से पूरी तरह से अलग हो रहा हूँ। उनका इस्तीफा पार्टी के कामकाज को लेकर चल रही नाराजगी के बीच आया है। उनके पार्टी छोड़ने से शिवसेना को बड़ा झटका लग सकता है।

यूपी: भाजपा छोड़ सपा में आए पूर्व सांसद राजपाल सैनी

लखनऊ। पूर्व सांसद राजपाल सैनी शुक्रवार को भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हो गए। विभिन्न दलों के कई और नेताओं ने भी सपा की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर सपा अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि यह शुरुआत है। अभी दूसरे दलों के कई विधायकों का स्वागत करना शुरू नहीं किया है। कई दल हैं, जो मोलभाव कर रहे हैं। उनकी तरफ भी देखेंगे। सपा अध्यक्ष का इशारा सत्ताधारी गठबंधन में शामिल दलों की तरफ था। भाजपा, बसपा, आजाद समाज पार्टी, निषाद पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल छोड़कर कई नेता शुक्रवार को अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। सपा की सदस्यता ग्रहण करने वाले नेताओं में भाजपा नेता व बसपा से राज्यसभा सांसद रहे राजपाल सैनी, पूर्व सांसद श्यामाचरण गुप्ता के पुत्र विदुष अग्रहरि, क्षत्रिय महासभा बरेली मंडल के उपाध्यक्ष व बदायूं निवासी भाजपा नेता रवि प्रताप सिंह, भाजपा प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य व शामली निवासी हरवीर मलिक शामिल थे।

पीएफआई के संस्थापक को दिल्ली के अस्पताल में इलाज की मंजूरी

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आतंकवाद निरोधक कानून यूएपीए के तहत एक मामले में गिरफ्तार 'पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया' (पीएफआई) के संस्थापक अध्यक्ष ई. अबूबकर को शुक्रवार को कुछ शर्तों के साथ दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दे दी। अबूबकर को एक मामले में गैर कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया गया था। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले की खंडपीठ ने अबूबकर को यहां साकेत स्थित मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में अपने इलाज का खर्च उठाने का निर्देश दिया और कहा कि उसके साथ परिवार का एक सदस्य रहेगा। खंडपीठ ने कहा, "याचिकाकर्ता को उसके साथ जाने वाले व्यक्ति (पुलिसहमय) के लिए जरूरी शुल्क का भुगतान करना होगा। हम यह स्पष्ट करते हैं कि तीमारादार के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं होनी चाहिए। हम अस्पताल से अनुरोध करते हैं कि वह आगे के इलाज और अस्पताल में संभावित रूप से रुकने की अवधि के बारे में एक रिपोर्ट दायित्व करे। अस्पताल का खर्च याचिकाकर्ता द्वारा उठाना जाएगा।" न्यायमूर्ति सुंदरेश ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि अदालत चीजों के प्रति असंवेदनशील नहीं हो सकती और एक न्यायाधीश के तौर पर "आपको इसमें थोड़ी सहानुभूति भी दिखानी चाहिए।

अमेरिका में मंदिर पर हमले से भड़का एमईए, भारतीयों की सुरक्षा पर जताई चिंता

मुंबई। विदेश मंत्री एस. जयशंकर 20 अक्टूबर 2026 को मुंबई में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो के साथ वार्ता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसकी जानकारी दी। जयशंकर इस दौरान अमेरिका की स्वतंत्रता के 250 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में वह मुख्य अतिथि होंगे। दूसरी ओर, अमेरिका के इलिनॉय राज्य स्थित औरोरा शहर में एक हिंदू मंदिर को निशाना बनाकर गोलीबारी करने की साजिश पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने चिंता व्यक्त की है।

प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने

अमेरिका में भारतीय समुदाय और भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ बढ़ती नस्लीय घृणा, एंटी-इंडिया हेट और नफरती अपराधों के मामलों पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने अमेरिकी प्रशासन से मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को कड़ी सजा दी जाए और वहां रह रहे भारतीय नागरिकों व हिंदू समुदाय की सुरक्षा, संरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि अब निर्णायक कार्रवाई की जरूरत है।

वहीं, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल

नाहयान 19 और 20 अक्टूबर को मुंबई के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री एस. जयशंकर उनकी मेजबानी करेंगे। यह दौरा ऐसे समय हो रहा है, जब जयशंकर 20 अक्टूबर को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के साथ भी बातचीत करेंगे।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि पिछले करीब एक दशक से विदेशी नेताओं और मंत्रियों की मेजबानी दिल्ली से बाहर की जाती रही है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्पेन के प्रधानमंत्री की वडोदरा में, जर्मनी के चांसलर फेडरिक मर्ज की अहमदाबाद में और मॉरीशस के प्रधानमंत्री की



वाराणसी में मेजबानी की थी।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह भी कहा कि विदेश मंत्री जयशंकर ने पिछले दिनों संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री के साथ बातचीत की। इस चर्चा में व्यापार, ऊर्जा और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के

कल्याण सहित कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बात हुई। इसके अलावा, उन्होंने खाड़ी क्षेत्र में चल रहे घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही, हमारे विदेश मंत्री ने जॉर्जिया के विदेश मंत्री से मुलाकात की, जो अबू धाबी में आयोजित रायसीना डायलॉग में हिस्सा ले रहे थे। हमारे विदेश मंत्री ने भी इस संवाद में भाग लिया और कई सत्रों में अपने विचार रखे। इसके अलावा, उन्होंने आपस अल खैमाह के शासक से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने द्विपक्षीय मामलों पर चर्चा की और खाड़ी क्षेत्र की मौजूदा स्थिति का जायजा लिया।

वहीं, मालदीव परियोजना पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर

जायसवाल ने कहा, मालदीव के साथ हमारा गहरा विकास सहयोग है। मालदीव सरकार के अनुरोध पर, हमने 3000 करोड़ रुपये के करेंसी स्वेप (मुद्रा बदला-बदली) समझौते को पहली बार आगे (रोलओवर) बढ़ाने का फैसला किया है, जो 23 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगा। यह करेंसी स्वेप व्यवस्था अक्टूबर 2024 में हुए समझौते के तहत है। इस रोलओवर से मालदीव की वित्तीय स्थिरता को और मजबूती मिलेगी।

प्रधानमंत्री मोदी की कनाडा यात्रा पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, कनाडा की विदेश मंत्री हाल ही में दिल्ली आई थीं। उन्होंने

हमारे विदेश मंत्री से मुलाकात की और दोनों के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री की कनाडा यात्रा को लेकर भी चर्चा हुई। यात्रा की तारीखों पर अभी बातचीत चल रही है, और सही समय आने पर हम इस यात्रा की घोषणा करेंगे।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री की यह यात्रा, भारत-यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत द्विपक्षीय सहयोग के एक पहलुओं की समीक्षा करने का एक अवसर होगा।



राजनीति में नहीं होना चाहिए परिवारवाद: देवेंद्र यादव

भिलाई। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने नगर निगम चुनाव में कैंडिडेट और बीएसपी के निजीकरण को लेकर अपना रुख साफ किया। देवेंद्र यादव ने कहा कि भिलाई नगर निगम के महापौर चुनाव में उनके परिवार से कोई भी चुनाव नहीं लड़ेगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ना तो वे स्वयं चुनाव लड़ेंगे और ना ही उनके परिवार का कोई सदस्य महापौर का चुनाव लड़ेगा। देवेंद्र यादव ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से अपील करते हुए कहा कि पार्टी ऐसे कार्यकर्ताओं को टिकट दे, जो लंबे समय से जनता के बीच रहकर काम कर रहे हैं, जिनकी छवि अच्छी है और जो लगातार जनता की लड़ाई लड़ते रहे हैं। चुनाव में जमीनी कार्यकर्ताओं की मौका मिलना चाहिए, ताकि कार्यकर्ता जनता के लिए मेहनत करे और पार्टी भी उसके साथ मजबूती से खड़ी हो। वहीं भिलाई इस्पात संयंत्र को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार और बड़े उद्योग समूहों पर निशाना साधते हुए कहा कि अंबानी, अडानी, मित्तल और ज़िंदल कोई भी भिलाई इस्पात संयंत्र को नहीं खरब सकता। बीएसपी भिलाई की पहचान और लोगों की भावनाओं से जुड़ा है और वे इसे बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे और बिकने नहीं देंगे

धमतरी में दहशत फैलाने वाले तेंदुए को ग्रामीणों ने ही पकड़ा

धमतरी। लगातार हो रहे तेंदुए के हमले से परेशान ग्रामीणों ने खुद मोर्चा सभालते हुए अब तेंदुए को पकड़ को लिया है। धमतरी और कोडागांव जिले के सीमावर्ती इलाकों में पिछले कुछ दिनों से ग्रामीणों के बीच तेंदुए की दहशत बनी हुई थी। इसके बाद आमानारा गांव में लोगों ने तेंदुए को पकड़कर वन विभाग के हवाले कर दिया। तेंदुए के पकड़े जाने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। पिछले दो दिनों के भीतर तेंदुए के हमलों में करीब 15 लोगों के घायल होने की खबर है, जबकि एक महिला सहित दो लोगों की मौत की जानकारी भी सामने आई है। हालांकि, हमलों में घायलों और मृतकों की अंतिम संख्या की आधिकारिक पुष्टि किया जाना बाकी है। तेंदुए की लगातार मौजूदगी और अचानक लोगों पर हमले की घटनाओं ने पूरे इलाके में चिंता बढ़ा दी थी। बताया जा रहा है कि आमानारा गांव में भी तेंदुए ने चार ग्रामीणों पर हमला किया था। वहीं, सीतानदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र के कारीपानी और बस्तर बुडरा गांव में भी कई ग्रामीणों पर हमले की घटनाएं सामने आई थीं। इन अलग-अलग घटनाओं के पीछे इसी तेंदुए के होने की आशंका जताई जा रही है। तेंदुए के आतंक के चलते ग्रामीणों में डर का माहौल था और लोग घरों से निकलने में भी सतर्कता बरत रहे थे। हालात को देखते हुए आमानारा के ग्रामीणों ने खुद मोर्चा सभालते हुए तेंदुए को पकड़ लिया। ग्रामीणों की इस पहल के बाद क्षेत्र में राहत की उम्मीद जगी है। हालांकि, जंगली जानवर को पकड़ने के दौरान सावधानी बरतना बेहद जरूरी है, क्योंकि ऐसे हालात में जान का खतरा बना रहता है।

छत्तीसगढ़	प्रमुख समाचार	ग़रबा विवाद पर भूपेश बघेल की एंट्री, आरएसएस पर हमला
		दुर्गा। गरबा पंडाल में समुदाय विशेष के युवकों के प्रवेश को लेकर हुए विवाद के अगले ही दिन पूर्व सीएम बघेल उसी गरबा पंडाल में पहुंचे, जहां बीते दिन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और समिति पदाधिकारियों के बीच जमकर विवाद और धक्का-मुक्की हुई थी। दुर्गा नवनिर्माण समिति के गरबा उत्सव में पहुंचे भूपेश बघेल ने मां दुर्गा की महाआरती की। विवाद के मद्देनजर पंडाल और आस-पास के इलाके में पुलिस की चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था तैनात रही। महाआरती के बाद मीडिया से बातचीत में भूपेश बघेल ने गरबा विवाद को लेकर बजरंग दल और भाजपा पर तीखा राजनीतिक हमला बोला। छत्तीसगढ़ में शीतला माता, जवारा, सेवा गीत, डोंगरगढ़, दतेवाड़ा और रतनपुर महामाया के रूप में मां की आराधना होती है। दुर्गा पूजा बंगाल से आई, गरबा गुजरात से आया और देश के लोग मिलकर इसे मनाते हैं। यही भारत की एकता और विविधता है। समुदाय विशेष के युवकों के गरबा पंडाल में प्रवेश को लेकर बजरंग दल के विरोध पर बघेल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर हमला बोला।

एक ही पंडाल में कीजिए अलग-अलग देशों के शक्तिपीठ के दर्शन

धमतरी। नवरात्र पर्व के दौरान छत्तीसगढ़ के धमतरी का अनोखा पंडाल आकर्षण का केंद्र बना है। जालमपुर स्थित बालवीर दुर्गा उत्सव समिति ने इस बार ऐसा पंडाल तैयार किया है, जहां श्रद्धालु एक ही स्थान पर अलग-अलग देशों और क्षेत्रों से जुड़े शक्तिपीठों की झांकी के दर्शन कर रहे हैं। अस्था, धार्मिक इतिहास और आकर्षक सजावट ने लोगों का मन मोह लिया है। पंडाल की विशेषता ऐसी है कि इसे देखने के लिए शहर ही नहीं, बल्कि दूर-दराज से भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं।

पंडाल में प्रवेश करते ही श्रद्धालुओं को शक्तिपीठों से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं और माता सती की कथा की जानकारी मिलती है। इसके लिए प्रवेश द्वार के आसपास विशेष पोस्टर लगाए गए हैं। पूरे पंडाल को गुफानुमा स्वरूप दिया गया है, जिससे भीतर पहुंचते ही एक अलग तरह का आध्यात्मिक



वातावरण महसूस होता है। इसके बाद अलग-अलग देश में स्थित शक्तिपीठों की झांकी है। प्रत्येक शक्तिपीठ के ऊपर लगाए गए बैनर में उसके नाम, स्थान, धार्मिक महत्व और मान्यताओं का उल्लेख किया गया है, ताकि श्रद्धालु दर्शन के साथ-साथ इनके बारे में जानकारी भी प्राप्त कर सकें। पंडाल के अंतिम हिस्से में ब्रह्मदंड की थीम पर आधारित आकर्षक सजावट की गई है। यहां

मां जगदंबा की भव्य प्रतिमा श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। कमल पुष्प पर हवा में खड़ी दिखाई देने वाली मां दुर्गा की प्रतिमा को विशेष कलात्मक तरीके से सजाया गया है। रोशनी और सजावट के बीच यह दृश्य श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींच

रहा है। पंडाल में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि देश-विदेश में स्थित सभी शक्तिपीठों के दर्शन करने के लिए अलग-अलग स्थानों की यात्रा करनी पड़ती है, जिसमें काफी समय और धन खर्च होता है। ऐसे में एक ही जगह कई देवियों के दर्शन करना उनके लिए सुखद अनुभव है। पंडाल की अनूठी अवधारणा की चर्चा सोशल मीडिया

छत्तीसगढ़

खैर लकड़ी तस्करी पर बड़ी कार्रवाई: हिमाचल से आरोपी गिरफ्तार, 1.70 करोड़ कैश जब्त

महासमुंद। महासमुंद जिले में खैर लकड़ी के अवैध परिवहन, तस्करी और फर्जी एनओसी-बिलिंग के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से फर्जी बिलिंग सिंडिकेट के सक्रिय सदस्य और शिव ट्रेडर्स के संचालक सतपाल सिंह (67) को गिरफ्तार किया है। उनके ठिकाने से 1 करोड़ 70 लाख रुपये नकद जब्त किए गए हैं। बता दें कि अब तक हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा और मध्यप्रदेश सहित कई राज्यों में दबिश देकर 70 टन अवैध खैर लकड़ी भी जब्त किए गए हैं। महासमुंद पुलिस की विशेष टीम ने हिमाचल प्रदेश में उन ठिकानों पर दबिश दी, जहां खैर लकड़ी की तस्करी से अर्जित रकम को खपाने में मदद की जा रही थी। इस दौरान पुलिस ने मनीष अग्रवाल और संजय छाबड़िया से जुड़े अवैध कारोबार से संबंधित 1 करोड़ 70 लाख रुपये नकद बरामद कर जब्त किए। इससे पहले 7 सितंबर 2026 को आरोपी मनीष अग्रवाल के ग्राम मुड़घार, थाना सरसीवा स्थित मकान पर दबिश देकर 81 लाख रुपये नकद जब्त किए गए थे। पुलिस ने 10 अक्टूबर 2026 को हरियाणा के गुरुग्राम जिले के पटौदी तहसील अंतर्गत ग्राम बहोड़ा कलां स्थित श्री बालाजी ट्रेडिंग फर्म के गोदाम में तलाशी ली। यह फर्म आरोपी मनीष अग्रवाल से संबंधित बताई गई है। तलाशी के दौरान गोदाम से लगभग 15 टन अवैध खैर लकड़ी बरामद हुई, जिसे पुलिस ने जब्त कर



लिया। पुलिस के अनुसार, ओडिशा, मध्यप्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में अलग-अलग ठिकानों पर की गई कार्रवाई के दौरान अब तक कुल 70 टन अवैध खैर लकड़ी जब्त की जा चुकी है। इस प्रकरण में पुलिस ने 12 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के कालाअंब से 67 वर्षीय सतपाल सिंह को गिरफ्तार किया। वह शिव ट्रेडर्स फर्म का संचालक है। पुलिस ने आरोपी को सिरमौर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय में पेश कर ट्रांजिट रिमांड प्राप्त किया और उसे महासमुंद लाया। अब उसे न्यायिक रिमांड के लिए संबंधित न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पुलिस की विवेचना के अनुसार, सतपाल सिंह ने अपनी फर्म शिव ट्रेडर्स के माध्यम से अखिलेश सिंघल, पारितोष मिश्रा, मनीष अग्रवाल, संजय छाबड़िया और अन्य आरोपियों के साथ आपराधिक षड्यंत्र किया। जांच में आरोप है कि वास्तविक खैर लकड़ी की आपूर्ति के बिना विभिन्न फर्मों से फर्जी बिल तैयार कराए गए। इन बिलों को वैध दिखाने के लिए वन

विभाग के फर्जी ट्रांजिट पास तैयार किए गए और एचएसएन कोड का दुरुपयोग किया गया। पुलिस के अनुसार, वित्तीय लेन-देन की जांच में पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंक खातों के माध्यम से कई बार करोड़ों रुपये के भुगतान किए जाने की जानकारी सामने आई है। इन लेन-देन की भूमिका और पूरे नेटवर्क की जांच जारी है। इस मामले की शुरुआत वन परिक्षेत्र अधिकारी पिथौरा की शिकायत के बाद हुई। शिकायत में 23,350 किलोग्राम खैर लकड़ी के अवैध परिवहन के लिए इस्तेमाल की गई एनटीपीएस एनओसी में कूटरचना और धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। इस आधार पर थाना पिथौरा में 9 जुलाई 2026 को अपराध दर्ज किया गया। प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), आर्म्स एक्ट और भारतीय वन अधिनियम, 1927 की संबंधित धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई।महासमुंद पुलिस इस मामले में पहले पारितोष मिश्रा और अखिलेश सिंघल को 14 सितंबर 2026 को गिरफ्तार कर चुकी है।

कॉलेज में एबीवीपी का प्रदर्शन, मूलभूत समस्याओं का निराकरण करने की मांग

गरियाबंद। पंडित श्यामशंकर मिश्र महाविद्यालय देवभोग में मूलभूत समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मोर्चा खोल दिया है। पहले कॉलेज प्रबंधन को अल्टीमेटम दिया गया, लेकिन मांगों पर ठोस पहल नहीं होने का आरोप लगाते हुए विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक क्षितिज नारायण तिवारी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कॉलेज का घेराव कर दिया। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को समझाइश देकर शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन विद्यार्थी अपनी मांगों पर डटे रहे। कॉलेज घेराव के दौरान पुलिस प्रशासन ने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को समझाइश देकर आंदोलन समाप्त करने का प्रयास किया। हालांकि, विद्यार्थी अपनी मांगों के निराकरण की मांग पर अड़े रहे। उनका कहना था कि जब तक महाविद्यालय की समस्याओं पर ठोस पहल नहीं होती, तब तक वे पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। प्रदर्शन के बीच महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. वाणा ठाकुर पहुंचने के बाद विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं और प्राचार्य के बीच मांगों को लेकर बातचीत हुई। काफी जद्दोजहद के बाद कार्यकर्ताओं ने प्राचार्य के समक्ष अपनी समस्याएं और मांगें रखीं। हालांकि, बातचीत के दौरान मांगों के निराकरण



को लेकर कोई ठोस सहमति नहीं बन पाई। इसके बाद विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता महाविद्यालय परिसर में ही बैठ गए। इससे आंदोलन का रुख और स्पष्ट हो गया। विद्यार्थी परिषद का कहना है कि लंबे समय से विद्यार्थियों को मूलभूत सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन पूर्व में ज्ञापन और आंदोलन के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। विद्यार्थी परिषद ने महाविद्यालय में पुस्तकालय के लिए पर्याप्त पुस्तकें, स्वच्छ पेयजल के लिए वाटर कूलर, शौचालयों की मरम्मत और साफ-सफाई, दोपहिया वाहनों के लिए पार्किंग, विद्यार्थियों के साथ कथित दुर्व्यवहार की शिकायतों पर कार्रवाई, हस्त इकाई को पुनः शुरू करने, सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे, परिसर में गुटखा खाकर शूनें पर रोक, कक्षाओं में पर्याप्त टेबल-कुर्सियां तथा खराब पंखों की मरम्मत सहित 10 मांगें रखी है।

कोरबा में आस्था के साथ स्थानीय लोक कला का अनोखा संगम

कोरबा। देश प्रदेश के साथ ही ऊर्जाधानी कोरबा में भी दुर्गा उत्सव की धूम है। शहर के अलग-अलग दुर्गा उत्सव समितियों ने आकर्षक पंडाल का निर्माण किया है। कहीं कोलकाता के कारीगरों ने पंडाल को आकार दिया है तो कहीं लोकल कलाकारों ने पंडाल का निर्माण किया है।

जेपी नगर कॉलोनी में बांस से बने खास दुर्गा पंडाल को कोलकाता के कारीगरों ने तैयार किया है। जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। एमपी नगर में भी आकर्षक दुर्गा पंडाल का निर्माण किया गया है। शिवाजी नगर में छतरी की थीम पर दुर्गा पंडाल को सजाया गया है। रास्ते में छतरी का इस्तेमाल कर अनोखे अंदाज में दुर्गा पंडाल और आसपास के इलाकों को सजाया गया है। खास तौर पर शाम के समय यहां और भी आकर्षक नजारा देखने को



मिलता है जो शहर वासियों को अपनी ओर खींच रहा है।

दुर्गा पूजा और दशहरा उत्सव समिति कोसाबाड़ी के अध्यक्ष दुर्गाश पांडे ने बताया कि कोसाबाड़ी में प्रत्येक वर्ष काशी के सुप्रसिद्ध पुरोहित पूजा करते हैं। प्रतिदिन सरस्वती पाठ विधि विधान से किया जाता है। रोज शाम को यह आयोजन होता है। बांस शिल्प से सजाया दुर्गा पंडाल जेपी कॉलोनी दुर्गा उत्सव समिति के तर्पण प्रकाश गोस्वामी ने कहा कि बस्तर आर्ट बोलिया या बांस शिल्प कहिए। इस तरह के बांस से बने खास पंडाल बनाते का हमने कोशिश किया है। 1958 से यहां दुर्गा पूजा हम बनाते आ रहे हैं।

लौह खदान में गाड़ियों में आग लगाने वाले पांच ओरापी गिरफ्तार

भानुप्रतापपुर। कांकेर जिले में लोहत्तर थाना क्षेत्र के लौह खदान में तीन गाड़ियों में आग लगाने के बाद छोड़े गए लाल सलाम पर्व का आखिरकार खुलासा हो गया है। पुलिस ने मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। मामला कांकेर जिले के लोहत्तर थाना क्षेत्र अंतर्गत चेमल के पास स्थित पुष्प ब्लॉक खदान का है। यहां खदान में चल रही तीन गाड़ियों में आग लगा दी गई थी। घटना स्थल लाल सलाम लिखा हुआ पर्चा छोड़े गये थे। वारदात के तरीके को लेकर मामले ने गंभीर रूप ले लिया, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें सहदेव तुलावी, प्रेम सिंह कोरेटी, ओम प्रकाश कचलाम, बुजलाल सलाम और शिवलाल तुलावी शामिल हैं। इनमें सहदेव तुलावी को कांड का मुख्य कर्ता-धर्ता बताया जा रहा है। घटना के पीछे जो बात सामने आई है, उसके अनुसार आरोपी अपने गांव में लौह खदान नहीं चाहते थे।

जर्जर सड़कों के विरोध में ग्रामीणों ने किया चक्काजाम

कटघोरा। कोरबा जिले में जर्जर सड़कों और उनसे उड़ने वाली धूल से परेशान ग्रामीणों का आक्रोश शुक्रवार को फूट पड़ा। लखनपुर सहित आसपास के ग्रामीणों ने सुतरी-बांकीमोंगरा-कटघोरा बाईपास में चक्काजाम कर दिया। ग्रामीण सुबह 9 बजे से सड़क पर धरने पर बैठ गए हैं। आंदोलन के कारण मार्ग पर यातायात प्रभावित हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि सड़कों की बदहाली और लगातार उड़ती धूल से आम लोग काफी परेशानी हैं। सड़क से गुजरने वाले वाहनों के कारण धूल के गुबार उठते हैं, जिससे राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लंबे समय से सड़क की मरम्मत नहीं हुई है। गुरुवार को इसी नाराजगी के चलते उन्होंने चक्काजाम कर प्रदर्शन करके का फैसला किया। आंदोलन में शामिल ग्रामीणों ने एसईसीएल और लोक निर्माण विभाग पर सड़क की समस्या को लेकर अनदेखी करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जर्जर सड़क के कारण लोगों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

कांकेर में पत्रकार को जान से मारने की धमकी

कांकेर। उत्तर बस्तर कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर में पत्रकार अभिषेक ठाकुर को जान से मारने की धमकी दी गई है। घटना के बाद पत्रकार और उनका परिवार भयभीत है। मामले को लेकर पहकार संघ भानुप्रतापपुर ने थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के मुताबिक 15 अक्टूबर की रात करीब 12 बजे से 16 अक्टूबर की सुबह 5 बजे के बीच अज्ञात व्यक्ति ने पत्रकार अभिषेक सिंह ठाकुर के घर के आंगन में धमकी भरा पत्र फेंका। पत्र में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए पत्रकारिता बंद करने की चेतावनी दी गई है। ऐसा नहीं करने पर जान से मारने और पहचान तक नहीं हो पाने जैसी धमकी दी गई है। पीड़ित पत्रकार ने थाना भानुप्रतापपुर में लिखित आवेदन देकर मामले की शिकायत की है। उन्होंने



बताया कि वह अपने समाचार रूप में निर्भीक होकर समाचार प्रकाशित करते हैं। इसी वजह से उन्हें निशाना बनाए जाने की आशंका है। घटना के बाद से उन्हें और उनके परिवार को अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही है। उन्होंने भविष्य में जान का खतरा होने की आशंका भी जताई है। पत्रकार को धमकी दिए जाने की घटना पर पत्रकार संघ भानुप्रतापपुर ने चिंता जताई है। संघ ने थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर भागने की गंभीरता से जांच करने, धमकी भरा पत्र भेजने वाले व्यक्ति की पहचान करने और उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इस मामले में पत्रकार संघ का कहना है कि इस तरह की घटनाएं स्वतंत्र और निर्भीक पत्रकारिता के लिए चिंताजनक हैं।

संक्षिप्त समाचार

जशपुर विधायक का कुशलक्षेम जानने अस्पताल पहुंचे पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री



श्री राजेश अग्रवाल ने गुरुवार को रायपुर स्थित एक निजी अस्पताल पहुंचकर जशपुर विधायक श्रीमती रायमुनि भगत से मुलाकात की और उनका कुशलक्षेम जाना। इस दौरान मंत्री श्री अग्रवाल ने विधायक श्रीमती भगत के स्वास्थ्य की जानकारी ली तथा उनके शीघ्र एवं पूर्ण स्वस्थ होने की कामना की। मंत्री श्री अग्रवाल ने विधायक श्रीमती भगत से संवाद करते हुए उनके स्वास्थ्य के प्रति अपनी चिंता और संवेदनशीलता व्यक्त की। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि श्रीमती भगत जल्द से जल्द पूर्णतः स्वस्थ होकर अपने परिवार, शुभचिंतकों और क्षेत्र की जनता के बीच लौटें तथा पूर्व की भांति जनसेवा एवं क्षेत्र के विकास से जुड़े कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाएं। पर्यटन मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि विधायक श्रीमती रायमुनि भगत जनसेवा के प्रति समर्पित जनप्रतिनिधि हैं। उन्होंने जशपुर क्षेत्र की जनता के प्रति उनके समर्पण और सक्रियता का उल्लेख करते हुए उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की।

छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य सेवाओं ने रचा जीवन रक्षा का नया अध्याय

रायपुर। छत्तीसगढ़ के दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और गंभीर मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के प्रयासों के बीच गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिला चिकित्सालय से एक सुख और प्रेरणादायक खबर सामने आई है। जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे महज 900 ग्राम वजन के एक नवजात शिशु को चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ ने लगभग दो माह तक लगातार उपचार एवं विशेष देखभाल प्रदान कर नया जीवन दिया है। अत्यंत कम वजन, समय से पूर्व जन्म, सांस लेने में परेशानी और गंभीर एनीमिया जैसी जटिल स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे इस नवजात को सफल चिकित्सा ने जिले में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं की उपयोगिता और चिकित्सकीय टीम के समर्पण को रेखांकित किया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने तथा दूरस्थ एवं आदिवासी अंचलों के नागरिकों तक गुणवत्तापूर्ण उपचार पहुंचाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसी दिशा में जिला चिकित्सालयों में उपलब्ध विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं ज़रूरतमंद परिवारों के लिए महत्वपूर्ण सहाय बन रही हैं। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिला चिकित्सालय में गंभीर अवस्था में भर्ती नवजात का सफल उपचार इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण है।

आईआरसीटीसी ने डिजिटल, थर्ड-पार्टी खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता ऑडिट के लिए क्यूसीआई के साथ साझेदारी की

रायपुर/बिलासपुर। प्रतिदिन लाखों रेल यात्रियों के लिए ऑन-बोर्ड भोजन के अनुभव को बढ़ाने के लिए एक बड़े कदम के तहत, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) के साथ एक रणनीतिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह महत्वपूर्ण साझेदारी आईआरसीटीसी द्वारा प्रबंधित सभी मोबाइल (ट्रेनों) और स्टैटिक (स्टेशन) कैटरिंग इकाइयों में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए एक कठोर, तकनीक-संचालित, स्वतंत्र थर्ड-पार्टी ऑडिट तंत्र स्थापित करती है। इस रणनीतिक गठबंधन के तहत, क्यूसीआई प्रमाणित पेशेवरों को गहन, औपचारिक प्रशिक्षण और अर्ध-वार्षिक निरीक्षण चक्र आयोजित करने के लिए तैनात करेगा। ये ऑडिट भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के वैधानिक नियमों और अंतरराष्ट्रीय पाक कला मानकों का सख्त अनुपालन लागू करेंगे। समझौता ज्ञापन पर आईआरसीटीसी के महाप्रबंधक/गुणवत्ता और परियोजनाएं, सुधीर वारियर और भारतीय गुणवत्ता परिषद के प्रधान सलाहकार/प्रमुख-पीपीआईआई, सुब्रतो घोष, रामानन्द नागेंद्र शुक्ला, सीईओ, एनएबीएल और मोहित पांडी, सहायक महासचिव, भारतीय गुणवत्ता परिषद तथा राहुल हिमालयन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और मनोज कुमार शर्मा, निदेशक/कैटरिंग सेवाएं, आईआरसीटीसी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।

350 बालिकाओं और माताओं को स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के प्रति किया गया जागरूकता

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा गुरुवार को महासमुंद के अंबेडकर भवन, बागबाहरा रोड में कन्या पूजन से कन्या संरक्षण तक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लगभग 350 किशोरी बालिकाओं एवं माताओं ने सहभागिता की। आयोजन के माध्यम से बालिकाओं के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत करने के साथ उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत 101 कन्याओं के पूजन एवं कन्या भोज के साथ हुई। इसके बाद जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने बालिकाओं और माताओं को शारीरिक स्वास्थ्य, केंसर से बचाव, किशोरावस्था में होने वाले बदलाव, मानसिक स्वास्थ्य तथा बच्चों की सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी। बाल मनोचिकित्सक डॉ. गार्गी पांडेय ने बच्चों की सुरक्षा, उनसे संवाद करने के तरीके और व्यवहार के महत्व पर अपनी बात रखी।

लोक निर्माण विभाग के सचिव ने निर्माणाधीन सड़कों का किया निरीक्षण

मरम्मत और बीटी पैव कार्यों में तेजी के दिे निर्देश

रायपुर। लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल प्रदेश में सड़कों की गुणवत्ता को लेकर लगातार नजर बनाए हुए हैं। समय-समय पर निर्माणाधीन सड़कों का निरीक्षण कर अधिकारियों को ज़रूरी निर्देश देते रहे हैं। इस कड़ी में उन्होंने कोरबा जिले में निर्माणाधीन सड़कों का निरीक्षण कर उनकी प्रगति एवं गुणवत्ता का जायजा लिया। उन्होंने निर्धारित समय-सीमा में निर्माण कार्यों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के साथ उनकी कड़ी व नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुकेश कुमार बंसल ने कोरबा में विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में निर्माणाधीन सड़कों, पुल-पुलियों एवं भवन निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। कोरबा के कलेक्टर कुणाल दुदावत और लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता वीके भतपहरी भी इस दौरान मौजूद थे।



बंसल ने अधिकारियों को सड़कों के बीटी पैव मरम्मत के कार्यों में तेजी लाने तथा क्षतिग्रस्त सड़कों एवं पुल-पुलियों की मरम्मत प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए, ताकि लोगों की आवाजाही प्रभावित न हो तथा उन्हें सुविधा मिल सके। बंसल ने निर्माण कार्यों में आने वाली समस्याओं का समय पर निराकरण सुनिश्चित करने को कहा, जिससे कि निर्माण कार्यों की प्रगति प्रभावित न हो। निर्धारित समयवाधि में निर्माण कार्यों को पूर्ण कराकर लोगों को विकास कार्यों का लाभ जल्द दिलाएं।

लोक निर्माण विभाग के सचिव ने कोरबा जिले में कटघोरा-हरदीबाजार-बलौदा-अकलतरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तथा हरदीबाजार-तरदा-सर्वमंगला-इमलीछापर मार्ग का निरीक्षण किया। उन्होंने ध्यानचंद चौक से बजरंग चौक मार्ग तक निर्माणाधीन सीमेंट-कांक्रिट सड़क का भी निरीक्षण किया। उन्होंने 2.84 किलोमीटर लंबे इस सड़क के निर्माण की प्रगति की जानकारी ली और मौके पर मौजूद अधिकारियों एवं निर्माण एजेंसी को इसे शीघ्र पूर्ण करने को कहा।

निरीक्षण के दौरान लोक निर्माण विभाग के बिलासपुर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता आरके रात्रे, अधीक्षण अभियंता (वि/यां) सुरेश भूपल और कोरबा संभाग के कार्यपालन अभियंता जी.आर. जांगड़े सहित विभागीय अनुविभागीय अधिकारी मौजूद थे।

3 नई मेमू ट्रेनों के परिचालन को मंजूरी

■ वृजमोहन अग्रवाल ने उठाया था मुद्दा

रायपुर। नवरात्रि के दौरान छत्तीसगढ़ को रेल मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ को तीन नई मेमू ट्रेनों की सौगात दी है। इसमें एक तरफ जहां रायपुर से सुदूर आदिवासी अंचल रावघाट तक नई मेमू ट्रेन चलने जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर रायपुर से कुरुद के बीच भी नई मेमू ट्रेन संचालित होगी। नई ट्रेनों के परिचालन के लिए लंबे समय से प्रयासरत रायपुर सांसद वृजमोहन अग्रवाल को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्र लिखकर नई रेल सेवाओं की स्वीकृति की जानकारी दी है।

बता दें कि अब तक बस्तर संभाग में रेलगाड़ी केवल कांकरे जिले के ताड़ोकी तक ही चल रही थी, लेकिन अब इससे 17 किलोमीटर आगे रावघाट तक ट्रेन



का संचालन शुरू होने जा रहा है। रावघाट के लिए वव 2011 में रेल लाइन का काम शुरू हुआ था। रावघाट तक ट्रेन पहुंचने से इस पूरे सुदूर वनांचल क्षेत्र की तस्वीर बदलने की उम्मीद है। वहीं दूसरी ओर कुरुद तक रेल सेवा शुरू होने से भी लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

नई रेलगाड़ियों के परिचालन की मंजूरी दी गई है- गाड़ी सं. 68768 / 68769 : रायपुर - रावघाट मेमू। गाड़ी सं. 68772 / 68771 : रायपुर - कुरुद मेमू। गाड़ी सं. 68774 / 68773 : रायपुर - कुरुद मेमू।

इस सौगात पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सांसद वृजमोहन

अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताते हुए कहा कि हमारा निरंतर संकल्प रहा है कि क्षेत्र की जनता को बेहतर, सुगम और किफायती आवागमन के साधन सुलभ हों। मैंने रेल मंत्री से मेमू ट्रेनों के संचालन के लिए अनुरोध किया था, जिसके बाद इनके परिचालन को हरी झंडी मिल गई है। उन्होंने कहा कि रायपुर से रावघाट और कुरुद के बीच नई मेमू ट्रेनों के शुरू होने से दैनिक यात्रियों, नौकरीपेशा वर्ग, किसानों, व्यापारियों, विद्यार्थियों तथा सुदूर अंचल से राजधानी आने-जाने वाले मरीजों एवं आम नागरिकों को सीधी और त्वरित यात्रा सुविधा मिलेगी। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि क्षेत्र के व्यापारिक और सामाजिक संपर्क को भी नई मजबूती प्राप्त होगी।

रबी 2025 के अंतर्गत किसानों के लंबित फसल बीमा क्लेम का आगामी तीन कार्य दिवस में होगा भुगतान

■ 8 हजार 444 किसानों को मिलेगी लगभग 3.8 करोड़ रुपये की राशि

रायपुर। कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम के सख्त निर्देश पर रबी सीजन 2025 के अंतर्गत उद्यानिकी फसलों के लंबित प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम का भुगतान आगामी तीन कार्य दिवस के भीतर किया जाएगा। किसानों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मंत्री श्री नेताम ने 16 अक्टूबर 2026 को विभागीय अधिकारियों और बीमा अधिकारियों की बैठक लेकर लंबित प्रकरणों की समीक्षा की तथा पात्र किसानों के बैंक खातों में बीमा राशि का भुगतान निर्धारित समय-सीमा में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस निर्णय से प्रदेश के 8 हजार 444 किसानों को लगभग 3.8 करोड़ रुपये की बीमा राशि का लाभ मिलेगा।

उल्लेखनीय है कि 15 अक्टूबर 2026 को राजनंदगांव जिले के डोंगरगांव विकासखंड अंतर्गत ग्राम चिहों के भ्रमण के दौरान किसानों ने मंत्री श्री नेताम से चर्चा करते हुए उद्यानिकी



फसलों के बीमा क्लेम का भुगतान नहीं होने की शिकायत की थी। किसानों ने अपनी समस्या से मंत्री को अवगत कराते हुए लंबित बीमा राशि का भुगतान कराने का आग्रह किया। इस पर मंत्री श्री नेताम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल पहल की और अगले ही दिन संबंधित विभागीय एवं बीमा अधिकारियों की बैठक लेकर भुगतान की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों के लंबित स्वीकृत क्लेम का भुगतान आगामी तीन कार्य दिवस के भीतर हर हाल में सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसानों को समय पर आर्थिक राहत मिल सके।

गौरतलब है कि पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रदेश के किसानों ने टमाटर, बैंगन, गोभी, प्याज और आलू सहित विभिन्न उद्यानिकी फसलों का बीमा

कराया है। विभागीय एवं बीमा अधिकारियों के अनुसार, रबी सीजन 2025 के लिए कुल 10 हजार 514 किसानों ने 15 हजार 298 आवेदन प्रस्तुत किए थे। परीक्षण के उपरांत इनमें से 8 हजार 444 किसानों के 14 हजार 344 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। इन स्वीकृत प्रकरणों के अंतर्गत किसानों को लगभग 3.8 करोड़ रुपये की बीमा राशि का भुगतान किया जाना है। मंत्री श्री नेताम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भुगतान प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब न हो तथा सभी आवश्यक औपचारिकताएं शीघ्र पूरी कर पात्र किसानों के खातों में राशि अंतरित की जाए। किसानों की समस्याओं का त्वरित निराकरण और उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकता है। किसानों द्वारा अपनी समस्या सामने रखे जाने पर मंत्री द्वारा तत्काल संज्ञान लेकर समयबद्ध भुगतान के निर्देश दिए जाने से लंबित बीमा क्लेम के निराकरण की प्रक्रिया को गति मिलेगी और संबंधित किसानों को आर्थिक राहत प्राप्त होगी।

बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार में शामिल होंगी द्रौपदी मुर्मू: सीएम साय

रायपुर।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जल्द ही छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाली हैं। द्रौपदी मुर्मू बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार में शामिल होंगी। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी है।

सीएम साय ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बस्तर दशहरा के लिए निमंत्रण दिए थे, जिसे उन्होंने स्वीकार किया था। ऐसे में अब राष्ट्रपति मुर्मू 22 और 23 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ आएंगी और बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार में शामिल होंगी।

वहीं आज मुख्यमंत्री हेल्ललाइन की समीक्षा बैठक होने वाली है। इसको लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्ललाइन योजना की समीक्षा बैठक है। हेल्ललाइन नंबर में लोग समस्या रजिस्टर कर सकते हैं। सरकार प्रयास कर रही है कि लोगों की समस्याओं का समाधान हो। छत्तीसगढ़ में गुरुवार



को महिला क्रिकेट टी20 मैच होने जा रहा है। इसको लेकर सीएम साय ने कहा कि पहली बार छत्तीसगढ़ में महिला क्रिकेट का आयोजन हो रहा है। भारत और जिम्बाब्वे के बीच मैच हो रहा है। महिलाओं के लिए मैच का टिकट फ्री है।

नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत ने स्पीकर और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सदन की समय सीमा का सदुपयोग की मांग की है। इस मामले में सीएम साय का कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष के यह अधिकार की बात है।

इसमें विधानसभा अध्यक्ष विचार करेंगे। एसआईआर पर कॉकरोच जनता पार्टी आज तिरंगा रैली निकाल रही है। इस मामले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि एसआईआर पर सीजेपी को ऑब्जेक्शन था। चुनाव आयोग ने पूरी तरह बात स्पष्ट कर दी है। अब इसमें ऑब्जेक्शन की बात नहीं है। वहीं सीएम साय ने आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो धर्म परिवर्तन करेंगे, उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

पीएससी घोटाला: क्या जेल से बाहर आएंगे सोनवानी?

■ हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

बिलासपुर। सीजीपीएससी भर्ती घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) के पूर्व अध्यक्ष तामन सिंह सोनवानी की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई, जिसमें दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई। सोनवानी नवंबर 2024 से जेल में बंद हैं। अब सभी की नजर हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी है।

दृढभरती घोटाला मामला वर्ष 2020 से 2022 के बीच आयोजित भर्ती परीक्षाओं और चयन प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। आरोप है कि इस दौरान आयोजित परीक्षाओं और इंटरव्यू में योग्य अभ्यर्थियों की अनदेखी कर प्रभावशाली राजनेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों से जुड़े लोगों का डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी और अन्य



महत्वपूर्ण पदों पर चयन किया गया। इस मामले के सामने आने के बाद छत्तीसगढ़ में सरकारी भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और चयन प्रणाली पर सवाल उठे थे।

मामले की गंभीरता को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार के अनुरोध पर जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपी गई थी। जांच के दौरान सीबीआई ने कई ठिकानों पर छापेमारी की और मामले से जुड़े दस्तावेज बरामद किए। जांच एजेंसी ने सीजीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष तामन



सिंह सोनवानी, तत्कालीन उप परीक्षा नियंत्रक ललित गणवीर समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया था।

इसके बाद

मामले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े

पहलुओं की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से की जा रही है। ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल किया है।

नवंबर 2024 से जेल में बंद तामन सिंह सोनवानी की जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी हैं और हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब अदालत के फैसले से स्पष्ट होगा कि सोनवानी को इस मामले में जमानत मिलती है या उन्हें फिलहाल जेल में ही रहना होगा।

सेवा संकल्प अभियान के तहत ‘आसरा’ एवं ‘करुणा’ अभियान से जुड़ी जन-जागरूकता गतिविधियां

रायपुर। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित ‘आसरा’ एवं ‘करुणा’ अभियान के तहत जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बेसहारा तथा होटल और सड़क पर रहने वाले बच्चों की पहचान कर उन्हें संरक्षण, विधिक सहायता एवं पुनर्वास सेवाओं से जोड़ना और असहाय वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के प्रति आम नागरिकों को जागरूक करना था।

कार्यक्रम में बच्चों एवं युवाओं को नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। उन्हें नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। उपस्थित नागरिकों को चाइल्ड हेल्ललाइन 1098 तथा सखी वन स्टॉप सेंटर 181 की सेवाओं के बारे में भी बताया गया।

नागरिकों को जानकारी दी गई कि चाइल्ड हेल्ललाइन 1098 संकटग्रस्त एवं ज़रूरतमंद बच्चों को सहायता और



संरक्षण उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वहीं, सखी वन स्टॉप सेंटर 181 हिंसा से प्रभावित महिलाओं को सहायता, परामर्श और अन्य आवश्यक सेवाएं प्रदान करता है।

कार्यक्रम के माध्यम से नागरिकों से ज़रूरतमंद बच्चों एवं असहाय वरिष्ठ नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता रखने, उनके अधिकारों का सम्मान करने और संकट की स्थिति में संबंधित विभागों तथा सहायता सेवाओं की जानकारी जागरूकता ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने की अपील की गई। साथ ही, कमजोर एवं ज़रूरतमंद वर्गों को विधिक सहायता और उपलब्ध संरक्षण सेवाओं से जोड़कर उनका सुरक्षित एवं सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने का संदेश दिया गया।

डिप्टी सीएम विजय शर्मा का सख्त रुख, लापरवाही करने वालों को नहीं मिलेगी कोई रियायत

पीएम आवास निर्माण में अनियमितता पर दो ठेकेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज

रायपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबों और ज़रूरतमंद परिवारों की आवास निर्माण में किसी भी प्रकार की अनियमितता, लापरवाही और हितग्राहियों के साथ धोखाधड़ी को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सख्त रुख अपनाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसा लेने की शिकायत पर कबीरधाम जिले में दो ठेकेदारों के खिलाफ खट्टकदर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। शर्मा ने स्पष्ट कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब परिवारों के पक्षे पर का सपना पूरा करने की महत्वपूर्ण योजना है। इसमें किसी भी स्तर पर गड़बड़ी या हितग्राहियों के हक की राशि का दुरुपयोग कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आवास निर्माण में कोताही बरतने और गरीबों के साथ धोखाधड़ी करने वालों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा है कि प्रत्येक ज़रूरतमंद परिवार को पक्का आवास मिले।

विशेष रूप से दूरस्थ वनांचलों में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति के परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि गरीबों के आवास निर्माण के लिए स्वीकृत राशि पर केवल हितग्राहियों का अधिकार है। इस राशि का दुरुपयोग करने अथवा आवास निर्माण के नाम पर हितग्राहियों को परेशान करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।

कबीरधाम जिले के विकासखंड बोड़ला अंतर्गत प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के हितग्राहियों से आवास निर्माण के नाम पर राशि लेकर निर्माण कार्य नहीं करने की शिकायतों पर दो अलग-अलग मामलों में कुल 9 हितग्राहियों से 5 लाख 9 हजार रुपए लेने की शिकायत सामने आई है। शिकायतों के आधार पर संबंधित ठेकेदारों के विरुद्ध थाना चिल्फी एवं थाना तरेगांव जंगल में अपराध दर्ज किया गया है। ग्राम पंचायत



राजाद्वार के पांच हितग्राहियों से आवास निर्माण के नाम पर कुल 3 लाख 20 हजार रुपए लेने और निर्माण कार्य नहीं करने के मामले में ठेकेदार कुमार मेरावी के विरुद्ध 14 अक्टूबर को थाना चिल्फी में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 318(4) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। ग्राम राजाद्वार निवासी देवसिंह से 60 हजार रुपए, मंभोर बाई से 60 हजार रुपए, पुसीया बाई से 60 हजार रुपए, कौशिल्या बाई से 80 हजार रुपए तथा ननकी बाई से

60 हजार रुपए आवास निर्माण के नाम पर लिए गए थे। शिकायत के अनुसार लगभग डेढ़ वर्ष बीतने के बाद भी न तो आवास निर्माण किया गया और न ही हितग्राहियों की राशि वापस की गई। इसके बाद हितग्राहियों की लिखित शिकायत पर ठेकेदार के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया।

इसी प्रकार विकासखंड बोड़ला की ग्राम पंचायत आमनारा में प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के चार हितग्राहियों से आवास निर्माण के नाम पर राशि लेने की शिकायत पर ठेकेदार तुमेश गोड़ के विरुद्ध 13 अक्टूबर को थाना तरेगांव जंगल में एफआईआर दर्ज की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बैसाखू बैगा से 64 हजार रुपए, सुकोर बाई से 60 हजार रुपए, सोनिया बाई से 45 हजार रुपए तथा रानी बाई से 20 हजार रुपए सहित कुल 1 लाख 89 हजार रुपए लेने की शिकायत दर्ज कराई गई है। इस मामले में थाना तरेगांव जंगल में अपराध क्रमांक 420 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना केवल मकान निर्माण की योजना नहीं, बल्कि गरीब परिवारों के जीवन में सुरक्षा, सम्मान और स्थायित्व लाने का माध्यम है। विशेष पिछड़ी जनजाति के परिवारों के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत आवास निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति गरीब और ज़रूरतमंद हितग्राहियों को बहला-फुसलाकर उनकी आवास राशि का दुरुपयोग करता है, तो यह अत्यंत गंभीर मामला है।

उन्होंने कहा कि आवास निर्माण के लिए स्वीकृत राशि का सदुपयोग सुनिश्चित करना और हितग्राहियों की समय पर आवास उपलब्ध कराना आवश्यक है। इसमें किसी भी स्तर पर अनियमितता सामने आने पर संबंधित जिम्मेदारों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। गरीबों के अधिकारों और उनके हितों की रक्षा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

पंजाब में ‘एसआईआर’ का विरोध और वास्तविक तथ्य

इकबाल सिंह चन्नी

पंजाब में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एस.आई.आर.) को लेकर राजनीतिक माहौल गर्माया हुआ है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी द्वारा मतदाताओं के नाम काटे जाने पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जबकि भाजपा का तर्क है कि मतदाता सूचियों को सही और अपडेट रखना निष्पक्ष चुनावों के लिए आवश्यक है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पंजाब सहित विभिन्न राज्यों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की गई। पंजाब में भी घर-घर जाकर मतदाताओं के ब्यौरे का सत्यापन करने की प्रक्रिया 25 जून से 3 अगस्त, 2026 तक चली। इसके बाद 13 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की गई। इस सूची में से लगभग 20,66,635 नाम घटे हुए सामने आए, जिससे राजनीतिक दलों में चिंता पैदा होना स्वाभाविक था। चुनाव अधिकारियों द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, पंजाब में पहले दर्ज मतदाताओं की संख्या लगभग 2.14 करोड़ थी। इनमें से 1,93,94,408 मतदाताओं के एन्च्युरेशन फॉर्म प्राप्त हुए, जो कुल मतदाताओं का 90.37 प्रतिशत बनते हैं। बाकी 20,66,635 नामों के बारे में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 9,44,131 व्यक्ति स्थायी रूप से अन्य स्थानों पर चले गए थे, 5,74,568 मृतक दर्ज थे, 4,12,715 व्यक्ति अनुपस्थित या मिले नहीं और 1,19,145 डुप्लीकेट प्रविष्टियां थीं। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि वोट घटने के कई अलग-अलग कारण थे लेकिन विपक्षी दलों द्वारा इस तरह दर्शाया जा रहा था जैसे सभी 20,66,635 वोट गलत तरीके से हटाए गए हों। कांग्रेस की आपत्ति है कि इस प्रक्रिया के दौरान किसी भी योग्य नागरिक का वोट नहीं काटा जाना चाहिए। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा बड़झड़ा ने पार्टी के ब्लॉक स्तरीय प्रतिनिधियों को सूचियों की जांच करने के लिए कहा था। दूसरी ओर, आम आदमी पार्टी के नेता बलतेज पन्नू ने भी सूचियों की जांच करने और नाम हटे होने की स्थिति में लोगों को पुन् पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए कहा। अकाली दल के नेता दलजीत सिंह चीमा ने भी सूचियों की जांच करने और आपत्तियां दर्ज कराने की बात कही। इससे स्पष्ट है कि नामों का सत्यापन केवल एक पार्टी का नहीं, बल्कि सभी पार्टियों और मतदाताओं के हित का मामला है। भाजपा का पक्ष है कि सही मतदाता सूची लोकतंत्र की बुनियादी आवश्यकता है। मृत व्यक्तियों के नाम, डुप्लीकेट प्रविष्टियों और स्थायी रूप से पता बदल चुके लोगों के पुराने रिकॉर्ड की पहचान करना चुनाव प्रबंधन का उत्तरदायी काम है। हिस्सा है। लेकिन इसके साथ यह सुनिश्चित करना भी अनिवार्य है कि कोई योग्य मतदाता केवल दस्तावेजी गलती, पते के बदलाव या रिकॉर्ड में अंतर के कारण अपने अधिकार से वंचित न रह जाए। किसी पुराने रिकॉर्ड से नाम न मिलना अपने आप में किसी नागरिक की अयोग्यता का अंतिम प्रमाण नहीं हो सकता। इसीलिए ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद दावों और आपत्तियों के लिए 13 अगस्त से 12 सितम्बर तक का समय दिया गया था। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार लगभग 12.80 लाख मतदाताओं के रिकॉर्ड को 2003 की मतदाता सूची से मिलाया नहीं जा सका था। इन्हें सीधे तौर पर अयोग्य करार देने की बजाय सत्यापन के लिए नोटिस और दस्तावेजों की जांच की प्रक्रिया रखी गई। इसके बाद ऐसे मामलों का निपटारा करना चुनाव प्रशासन की जिम्मेदारी है। 23 सितम्बर को प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार 22.69 लाख मतदाताओं के रिकॉर्ड में पाई गई तार्किक गड़बड़ियों में से 22.41 लाख, यानी 98.77% मामलों का सत्यापन किया जा चुका था। यह आंकड़ा दर्शाता है कि जानें की प्रक्रिया आगे बढ़ी लेकिन इससे हर व्यक्ति के वोट के बारे में अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

भारतीय दार्शनिक सम्प्रदाय

19- थेरावाद या प्रारम्भिक पाली बौद्धधर्म

गताक्त से आगे...

हर्ष की बात है कि स्वर्गीय श्री धर्मानन्द कौशाम्बी ने इस ग्रन्थ की विशुद्धिम्गम दीपिका नामक टीका की है, जो निरसंदेह एक महत्त्वपूर्ण रचना है।

(2) विशुद्धिम्गम तो थेरावाद सम्बन्धी सामान्य ग्रन्थ है, परन्तु थेरावाद के दर्शन और मानोविज्ञानशास्त्र से विशेषरूप से सम्बन्ध रखने वाला, ग्रन्थ अट्टुसालिनी है। अभिधम्मपिटक के अन्तर्गत धम्मसंगणि नामक दार्शनिक ग्रन्थ की बुद्धघोष रचित टीका का नाम ही अट्टुसालिनी है।

(3) परन्तु थेरावाद सम्बन्धी बौद्धदर्शन का सर्वप्रमुख आधार ग्रन्थ अनिरुद्ध कृत अभिधम्मत्थसंग्रह है । अनिरुद्ध भी बुद्धघोष के लगभग समकालीन ही थे। हर्ष की बात है कि श्री धर्मानन्द कौशाम्बी ने इस आधारग्रन्थ की भी एक टीका प्रकाशित की है।

थेरावाद का सिद्धान्त – यहां तक हमने थेरावाद



या प्रारम्भिक पाली बौद्धधर्म के साहित्य और विशेषकर दार्शनिक साहित्य का निरूपण किया है। इस थेरावाद के आधारभूत सिद्धान्त वही हैं जो जो मूल बौद्धधर्म के सिद्धांत समझे जाते हैं। भारतीय दर्शन शास्त्र की भूमिका में हमें उन सिद्धान्तों के विशेष विवेचन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वैदिक दार्शनिक सम्प्रदाय के लेखकों ने जहाँ शून्यवाद, विज्ञानवाद या दिङ्माग का जगह जगह उल्लेख किया है और थोड़ा बहुत संकेत सर्वास्तिवाद के सिद्धान्तों के विषय में भी किया है, वहां पाली के थेरावाद सम्बन्धी सिद्धान्तों का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं है। परन्तु फिर भी बौद्धधर्म के आधारभूत थेरावाद या प्राचीन बौद्धधर्म के सिद्धान्तों का संक्षिप्त विवरण देना आवश्यक ही है। जरा और मृत्यु के रूप में दुःख को देखकर उसका कारण और नाश का उपाय ढूँहने के लिए बुद्ध घर छोड़कर निकले थे।

क्रमशः ...

हुतियों को नियंत्रित करने में सऊदी अरब, अमेरिका क्यों विफल हो रहे हैं?

कमलेश पांडे

खाड़ी देशों में ईरान पर जोरदार हमला करके अमेरिका-इजरायल ने जो आगे भड़काई, उसकी भारी कीमत आज उसके समर्थक चुका रहे हैं। जब ईरान ने अपनी सधी हुई रणनीति से और रूस व चीन के बल पर अमेरिका-इजरायल को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, तो उन्होंने अपनी सैन्य कार्रवाई रोक ली। इधर ईरान समर्थित यमन के हूती विद्रोहियों ने जब सऊदी को निशाने पर लिया और ताबड़तोड़ हमले शुरू किए, तो उनके विरुद्ध अमेरिका, सऊदी अरब और इस्लामिक नाटो की सैन्य क्षमता पर सवाल उठने लगे हैं। आधुनिक हथियारों, उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के बावजूद हूती विद्रोही सऊदी अरब के लिए सुरक्षा चुनौती बने हुए हैं।

जिस तरह से अक्टूबर 2026 में रियाद के किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमले हुए और लाल सागर के समुद्री मार्गों को लेकर तनाव बढ़ा, उसने इस संकट की ओर गंभीर बना दिया है। आइए हम आपको इसके पीछे के दस अहम सवाल समझाएंगे, जो आगे दिए हुए हैं। इससे पहले एक मीडिया की 12–13 अक्टूबर की रिपोर्टों में सऊदी हवाई सुरक्षा की कमजोरियों और हुतियों की बढ़ती क्षमताओं का उल्लेख किया गया है, उसकी चर्चा करते हैं। यही वजह है कि इस संकट को समझने के लिए तीन सवाल महत्त्वपूर्ण हैं–

एक, अमेरिका जैसी महाशक्ति हुतियों को निर्णायक रूप से नियंत्रित क्यों नहीं कर पा रही है? शायद इसलिए कि उनके ऊपर ईरान और ईरान के ऊपर रूस व चीन का हाथ है। सभी मिलकर खाड़ी देशों से अमेरिकी पांव उखाड़ना चाहते हैं। इसलिए अमेरिका बेबस है।

दो, सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किये के बीच बने नए रक्षा समझौते की वास्तविक उपयोगिता क्या है? दरअसल, यह अमेरिकी इशारे पर भारत के विरुद्ध बंवाया गया संगठन है। लेकिन इनकी आर्थिक और सैन्य क्षमता ईरान से सीधा टकराने की

ज्ञान/मीमांसा

ज्ञानेश के इस्तीफा की मांग, विपक्ष का हठ और संस्थाओं की साख

अशोक भाटिया

भारतीय लोकतंत्र का सबसे मजबूत खंभा उसकी निष्पक्ष चुनाव प्रणाली रही है। वैश्विक पटल पर जब भी भारत की लोकतांत्रिक परिपक्वता की मिसाल दी जाती है, तो निर्वाचन सदन यानी भारत निर्वाचन आयोग की भूमिका को अग्रिम पंक्ति में रखा जाता है। किंतु, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर वर्तमान में जो अभूतपूर्व राजनीतिक और संवैधानिक गतिरोध पैदा हुआ है, उसने इस प्रतिष्ठित संस्था की निष्पक्षता को इतिहास के सबसे गंभीर दोराहे पर ला खड़ा किया है। देश की राजनीति इस समय इस सवाल को लेकर सुलग रही है कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त का इस्तीफा मांगना कांग्रेस और समूचे विपक्ष की एक सैद्धांतिक लड़ाई है, या फिर यह उनकी सीधी-समझी राजनीतिक विवशता और नैरेटिव सेट करने की मजबूरी का हिस्सा है? केरल विधानसभा द्वारा देश के इतिहास में पहली बार किसी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करना और कांग्रेस द्वारा सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मोर्चा खोलना यह दर्शाता है कि यह विवाद महज एक प्रशासनिक विसंगति नहीं, बल्कि एक गहरे राजनीतिक संग्राम का रूप ले चुका है।

इस विवाद की शुरुआत द ईंडियन एक्सप्रेस की एक खोजी रिपोर्ट से हुई, जिसने निर्वाचन आयोग के भीतर के बंद दरवाजों के मतभेदों को सार्वजनिक कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार, मतदाता सूची के व्यापक पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर आयोग के भीतर ही गहरा बिखराव था। दावा किया गया कि अन्य दो चुनाव आयुक्तों—सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी—ने पिछले 10 महीनों में मतदाता सूची से नाम हटाने, नए नाम जोड़ने और डेटा प्रबंधन की प्रक्रियाओं पर करीब 14 बार औपचारिक और लिखित आपत्तियां दर्ज कराई थीं। लोकतंत्र का स्थापित नियम और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस यह स्पष्ट करती हैं कि निर्वाचन आयोग में कोई भी निर्णय बहुमत या सर्वसम्मति से होना चाहिए। विपक्ष का सीधा आरोप है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अन्य आयुक्तों की चिंताओं और आपत्तियों को दरकिनार करते हुए एकतरफा फैसले लिए। जब किसी संवैधानिक संस्था के भीतर ही इस स्तर का आंतरिक असंतोष और अविश्वास सहज पर आ जाए, तो उसकी साख पर उंगलियां उठना स्वाभाविक है।

विपक्ष के इस उग्र आंदोलन के केंद्र में



स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया है। इस कवायद के तहत देश के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों से लगभग 13.30 करोड़ नामों को हटा दिया गया है, जो भारत के कुल मतदाता वर्ग का लगभग 13 प्रतिशत है। चुनाव आयोग का तर्क है कि यह प्रक्रिया बोगस, दोहरे और अपात्र मतदाताओं को हटाने तथा सूची को शुद्ध करने के लिए की गई वैधानिक प्रशासनिक कार्रवाई है। इसके विपरीत, कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इसे कुत्रिम हेरफेर और वोट चोरी की संज्ञा दे रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया के जरिए जानबूझकर एक निश्चित वर्ग और विपक्ष के पारंपरिक झुकाव वाले मतदाताओं के नाम काटे गए हैं ताकि आगामी चुनावों के परिणामों को प्रभावित किया जा सके। राहुल गांधी का दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन, पुलिस द्वारा उन्हें हिरासत में लिया जाना और शशि थरूर जैसे नेताओं द्वारा संसद में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने की चेतावनी यह स्पष्ट करती है कि विपक्ष इस मुद्दे को तार्किक परिणति तक ले जाने के लिए आमादा है।

इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प और सूक्ष्म पहलू यह है कि आखिर कांग्रेस ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे पर इस कदर क्यों अड़ी है? क्या ज्ञानेश कुमार का पद से हट जाना ही इस समस्या का अंतिम समाधान है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना ​​है कि इस आक्रामक रुख के पीछे कांग्रेस की रणनीतिक और राजनीतिक मजबूरियां छिपी हुई हैं। लगातार चुनावी चुनौतियों और कई राज्यों में सत्ता से बाहर रहने के बाद, कांग्रेस के लिए अपने कार्यकर्ताओं के भीतर यह विश्वास जगाना जरूरी है कि उनकी वैचारिक या सांगठनिक कमजोरी के कारण पराजय नहीं हो रही है। ज्ञानेश कुमार पर सीधा और तीखा हमला करके राहुल गांधी देश के मानस में यह नैरेटिव सेट करने में सफल हो रहे हैं कि हम चुनाव मैदान में परास्त नहीं हो रहे, बल्कि सरकारी मशीनरी

विष्णु ने कैसे किया कालनेमि का अंत, चक्र से क्यों काटने पड़े सौ भयंकर मस्तक?

आशुतोष गर्ग

देवताओं और दानवों के बीच एक बार ऐसा भयंकर युद्ध हुआ, जिसकी कल्पना करना भी कठिन था। दानवों की ओर से कालनेमि नामक एक अत्यंत शक्तिशाली असुर युद्ध का नेतृत्व कर रहा था। वह केवल बलवान ही नहीं, बल्कि अपने अद्भुत आकार और भयानक स्वरूप की वजह से सभी के लिए भय का कारण था। उसकी सौ भुजाएं थीं और प्रत्येक हाथ में एक आयुध था। उसके सौ मुख और सौ मस्तक उसे किसी विशाल पर्वत के समान बना देते थे।

दानवों ने कालनेमि को अपना सेनापति बनाया और उसके पीछे युद्धभूमि में उतर पड़े। दूसरी ओर, चंद्रमा और सूर्य के प्रकाश से दीप्त देवसेना सजकर तैयार थी। अग्नि और वायु भी देवताओं के साथ

थे और पूरी सेना भगवान नारायण के संरक्षण में थी। दोनों सेनाएं जब आमने-सामने आईं तो ऐसा लगा, जैसे प्रलय के समय आकाश और पृथ्वी एक-दूसरे से टकरा रहे हों।

युद्ध आरंभ होते ही चारों ओर अस्त्र-शस्त्रों की वर्षा होने लगी। देवता वज्र और लोहे के परिघ चलाने लगे, तो दानव तलवारों और भारी गदाओं से उनका सामना करने लगे। किसी के शरीर पर बाणों की चोट लगी, किसी के अंग गदा के प्रहार से टूट गए और अनेक योद्धा घायल होकर भूमि पर गिर पड़े। इसी बीच कालनेमि ने अपना विशाल रूप धारण कर लिया।

क्रोध से उसकी भाँहें तन गईं और मुख से अग्नि की लपटें के समान प्रचंड ज्वाला निकलने लगी। उसकी भुजाओं के प्रहार से



देवता, यक्ष, गंधर्व और नाग तक घायल होकर गिरने लगे।

अपने अहंकार में वह स्वयं को तीनों लोकों का स्वामी समझने लगा। कालनेमि ने निश्चय किया कि वह श्रीहरि को पराजित करके वैकुंठ पर अधिकार कर लेगा।

भगवान विष्णु के सामने पहुंचा। श्रीहरि गरुड़ पर विराजमान थे और उनके हाथ में कौमोदकी गदा थी। कालनेमि ने श्रीहरि को देखकर कटु वचन कहे। कालनेमि ने कहा, ‘तुमने अनेक असुरों और उनके पूर्वजों का संहार किया है। तुम देवताओं के रक्षक और दानवों के घोर विरोधी हो।’

विष्णु जी ने शांत स्वर में कहा, ‘कालनेमि! तुम्हारे पास बल से अधिक अहंकार है। तुमने देवताओं के अधिकार छीनकर धर्म की मर्यादा तोड़ी है। आज

तुम्हारे अधर्म का अंत हो जाएगा।’ इस बीच क्रोध में कालनेमि ने एक विशाल गदा उठाकर गरुड़ पर प्रहार किया। गदा गरुड़ के मस्तक पर लगी। गरुड़ को घायल देखकर विष्णु जी क्रोध से लाल हो उठे। उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र उठाया। सुदर्शन सूर्य के समान चमक रहा था।

श्रीहरि ने चक्र चलाया और देखते ही देखते कालनेमि की सौ भुजाएं कटकर भूमि पर गिर गईं। फिर उसके सौ भयंकर मस्तकों को भी चक्र ने काट डाला। इसके बाद भी कालनेमि का विशाल धड़ कुछ समय तक युद्धभूमि में खड़ा रहा। तभी गरुड़ ने अपने विशाल पंख फैलाए और तीव्र गति से कालनेमि की ओर झपटे। उन्होंने अपनी छाती के प्रचंड आघात से उस दानव को धरती पर गिरा दिया। कालनेमि के मरते ही देवताओं और ऋषियों ने भगवान विष्णु की जय-जयकार की।

आज का इतिहास

1905 लार्ड कर्जन द्वारा बंगाल का प्रथम विभाजन।

1456 उत्तरी यूरोप के विश्वविद्यालय ग्रीसवाल्ड विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी थी।

1806 हैती के सम्राट जैक्स प्रथम की उनके दमनकारी शासन के बाद हत्या कर दी गयी थी।

1870 कलकत्ता बंदरगाह को एक संवैधानिक निकाय प्रबंधन के तहत लाया गया था।

1888 थामस अल्वा एडिसन ने ऑप्टिकल फोनोग्राफ के पेटेंट के लिए आवेदन किया था।

1912 बुल्गारिया, यूनान और सर्बिया ने ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई की घोषणा की थी।

1917 प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने पहली बार जर्मनी पर हवाई हमले किये थे।

1933 वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन नाजी जर्मनी से अमेरिका चले गये थे।

1939 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने ब्रिटिश क्षेत्र पर पहला हमला किया।

1941 द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पनडुब्बी ने एक अमेरिकी पोत पर हमला किया था।

1951 पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की रावलपिंडी में गोली मारकर हत्या की गई।

1959 राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना।

1964 चीन ने अपना पहला परमाणु विस्फोट किया।

1979 मधर टेरेसा को शांति के लिये नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था।

2000 पश्चिम एशिया शांति वार्ता सम्पन्न, दोनों पक्ष बिल क्लिंटन के तीन सूत्रों पर सहमत हुए थे।

2003 चीन ने अंतरिक्ष में एशिया के पहले और रूस के बाद तीसरे देश के रूप में अंतरिक्ष में मानव भेजने में सफलता प्राप्त की थी।

2004 न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री क्लार्क भारत पहुँची थी।

2007 आयरिश लेखिका एनी एनराइट को उनके उपन्यास द गेदरिंग के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

2008 एकाधिकार व प्रतिबंधित व्यापार आयोग ने निजी एअर लाइंस, किंगफिशर और जेट एयरवेज़ के गठबंधन की जाँच के आदेश दिए थे।

2009 हंदी महासागर में स्थित मालदीव ने पानी के अंदर दुनिया की पहली कैंबिनेट बैठक कर सभी राष्ट्रों को ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से आगाह करने की कोशिश की थी।

उत्तर प्रदेश में नामांकन की चुनौतियां, अयोध्या चैलेंज और राजनैतिक भविष्य का संखनाद

અશોક ભાટિયા

भारतीय राजनीति का यह एक सर्वमान्य और समय-समय सिद्धांत है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ के गणसिद्धि सत्रों से होकर ही गुजरता है। उत्तर प्रदेश न केवल देश का सबसे बड़ा राज्य है, बल्कि यह वह राजनैतिक कुक्षेत्र भी है जहां राष्ट्रीय स्तर के बड़े-बड़े सियासी सूत्रमाओं का भाग्य तय होता है। वर्ष 2026 के इस उत्तराधारी में कदम रखते हो प्रदेश में अपाणी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगमियों अपने चरम पर पहुंच चुकी हैं और संपूर्ण राज्य एक बार फिर एक बड़े लोकतांत्रिक उत्सव और उसकी जटिलताओं के मुहाने पर खड़ा है। किसी भी चुनाव प्रक्रिया का सबसे पहला, महत्वपूर्ण और प्रशासनिक रूप से संवेदनशील पड़ाव नार्मलफ़ंड होता है, जो केवल एक कानूनी या प्रशासनिक औपचारिकता मात्र नहीं है, बल्कि यह किसी भी राजनैतिक दल की सांपादनिक शक्ति, आंतरिक अनुशासन और जमीनी रणनीति का लिटमस टेस्ट है। इस प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियां न केवल चुनाव आयोग और प्रशासन के धैर्य की परीक्षा लेती हैं, बल्कि यह विभिन्न राजनैतिक दलों के अस्तित्व और उनकी साख़ से भी जुड़ी होती हैं। इस बार, यह नामांकन प्रक्रिया सिर्फ़ कागजी कार्यवाहियों तक सीमित नहीं है, बल्कि सुवे के दो सबसे बड़े दिग्गजों—मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव—के बीच सीधे ७%नामांकन चैलेंज के रूप में लटकी हो चुकी है, जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत में एक अभूतपूर्व भूचाल ला दिया है।

इस राजनीतिक रस्साकशी का शुरुआत तब हुई जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या का दौरा किया और सारकूड़ भारतीय जनता पार्टी पर तीखा तंज कसते हुए दावा किया कि सपा द्वारा उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद बांध खाड़ा सर्वे पर सर्वे का रद्दी है और उस अयोध्या में भज्ज करने के लिए कोई उपाय कर प्रत्याशी ही नहीं मिल रहा है। अखिलेश ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीधे चुनौती दे डाली

कि अगर उन्हें अपनी लोकप्रियता और विकास कार्यों इतना ही भरोसा है, तो वे खुद आगामी विधानसभा चुनावों में योगी साहू से मैदान में उतरकर दिखाएँ। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने इस चुनौती को न सिर्फ स्वीकार किया, बल्कि इसे एक कदम आगे बढ़ाते हुए अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुनाव लड़ें और सार्वजनिक कार्यक्रम में साफ शब्दों में कहा कि आदित्यनाथ ने तो अखिलेश जी आयोग से चुनाव लड़ें और मैं भी लड़ूँगे, दोनों आमने-सामने नामांकन दाखिल एक बार अपनी किस्मत आजमा लें ताकि मामला हमारे लिए तय हो जाए। योंगे के इस सीधे प्रहार अखिलेश आयोग ने भी तुरंत प्रतिक्रिया दी और इस सभा मुकाबले को यह कहते हुए चलाने की कोशिश की भाजपा को हारने के लिए उनका एक युवा %पीडीएम% प्रहरी ही काफी है। इस जुबानी जंग ने यह साफ दिखाया है कि आगामी चुनावों में नामांकन का दौर कि हाई-वोल्टेज होने वाला है और दोनों खेमें द्वारा एक दूसरे की धरादी का यह सबसे आक्रामक रूप है।

किसी भी राजनीतिक दल के लिए चुनाव की घोषणा के बाद नामांकन का चरण सबसे अधिक तनावपूर्ण और आंतरिक संघर्षों से भरा होता है क्योंकि इच्छित घोषणा से लेकर नामांकन पर दाखिल करने के औपचारिक मिनट तक दलों के भीतर जो उथल-पुथल मचती है, सांगठनिक ढाँचे को हिलाकर रख देती है। टिकटों का मिलने से नाराज कार्यकर्ताओं और नेताओं का विद्रोह उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक कड़वा और अपरिवर्तनीय सच है, जहां नामांकन के ठीक पहले पक्षों में बदलाव, रातों-रात प्रतिद्वंद्वी पार्टी की सदस्यता ले लेने, निर्दलीय पक्षांश दाखिल कर देना या अपनी ही पार्टी में आधिकारिक उम्मीदवार का खेल बिगाड़ने के फैसले किसी डमी प्रत्याशी को खड़ा कर देना सबसे बड़ा सांगठनिक चैलेंज बन जाता है। भारतीय जनता पार्टी जैसी कैडर-आधारित पार्टी हो या समाजवादी पार्टी जैसे मजबूत क्षेत्रीय ताकत, आंतरिक असंतोख को दबाना और रुढ़े हुए पक्षों को मानाई देना इस समय दोनों ही खोमों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है, और जब बड़े

एक-दूसरे को सीधे नामांकन की चुनौती दे रहे हों, तो जमीनी कार्यकर्ताओं को अनुशासित रखना और अधिक मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही, चुनाव आयोग न हाल के वर्षों में नामांकन पत्रों की स्वरूपांतर और लफनामों की समीक्षा को अत्यधिक कड़ा कर दिया है, जिसके तहत शपथ पत्र में अपनी संपत्ति, आपराधिक इतिहास, शैक्षणिक योग्यता और वित्तीय देनदारियों का रसीद भर भी गलत विवरण देना पूरे नामांकन को निरस्त कर सकता है, जैसा कि हाल ही में संपन्न हुए राज्यसभा और विधान परिषद द्विपक्षीय चुनावों के दौरान कुछ निर्दलियों व छोटे दलों के उम्मीदवारों के पंचे खारिज होने से साबित भी हो चुका है।

राजनीतिक रूप से संवेदनशील राज्य में नामांकन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना जिला प्रशासनों और श्वश्रद्धाद्रूप महकमे के लिए किसी अगिंपरीक्षा से कम नहीं होता क्योंकि कलेक्टर और कमिश्नरी कार्यालयों के बाहर का दृश्य अक्सर राजनैतिक शक्ति प्रदर्शन के अखाड़ा बन जाता है। नामांकन दाखिल करने जाते समय उम्मीदवारों द्वारा भीड़ जुटाना, अपनी ताकत का अहसास कराना और गाड़ियों के लंबे काफिले ले जाना एक आम चर्चन बन चुका है, जिसके कारण चुनाव आयोग के कड़े नियमों के बावजूद कलेक्टर परिसर के बाहर समर्थकों का झुलम नियंत्रित करना पुलिस के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द साबित होता है और इस दौरान अल्पसंख्यका आचार संहिता के उल्लंघन के मामले सबसे ज्यादा दर्ज

होते हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिले राजनीतिक और सामाजिक रूप से अत्यधिक संवेदनशील माने जाते हैं, जहां नामांकन के दौरान प्रशिक्षित गुटों के बीच झड़प, नारेबाजी और कभी-कभी हिंसक टकराव की आशंका बनी रहती है, जिससे निपटने के लिए प्रशासन को चप्पे-चप्पे पर सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन कैमरों और भारी सशस्त्र कांस्टेबुलरी तथा अर्धसैनिक बलों की तैनाती करनी पड़ती है ताकि पूरी नामांकन प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। इस चुनौती माहौल में डिजिटल तकनीक जहां एक तरफ है, वहीं यह प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती भी बनकर उभरी है क्योंकि हाल के एफतों में सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश में पंचायत और स्थानीय निकायों में चुनावों के नामांकन और तारीखों को लेकर कई फर्जी और भ्रामक खबरें प्रसारित की गईं, जिनका खंडन करना और जनता के बीच सही सूचना पहुंचाना राज्य निर्वाचन आयोग के लिए एक अतिरिक्त प्रशासनिक चुनौती बन गया है।

वास्तव में, योगी और अखिलेश के बीच छिड़ा यह मतभेद युद्ध आगामी महासमर की नींव रख रहा है और मतभेद में जो भी सांठगठन फेरबदल या राजनैतिक यानबाजी हो रही है, वह मुख्य चुनाव के मद्देनजर ही की जा रही है, जिसमें सभी प्रमुख दलों के सामने अपनी-अपनी विशिष्ट चुनौतियाँ हैं। लगातार दो बार जीत की सत्ता पर काबिज रहने के बाद मुछामंत्री योगी गदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा के सामने सत्ता विरोधी गठन को कम करने और नए चेहरों को मौका देने की चुनौती होगी, और जब विधानसभा चुनाव के वास्तविक मतदान शुरू होंगे, तब मौजूदा विधायकों के टिकट आगामी या बदलने पर जो अंतरात्मा असंतोष पैदा होगा, उसे संभालना पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और योगी गदित्यनाथ के लिए सबसे बड़ा संकटमान होगा। दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी पिछले कुछ समय से अपने प्रतीकपीडीएम (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फार्मूले के खूब खुद को री-ब्रांड कर रही है, और अखिलेश यादव

का लिए चुनौती यह होगा कि एक ठो वितरण और नामांकन के समय इस सामाजिक समीकरण को जमीन पर कैसे उतारते हैं तथा अयोध्या जैसी प्रतीकात्मक और हाई-प्रोफाइल सीट पर योगी आदित्यनाथ की सोधी चुनौती का सामना करने के लिए वे अपने मौजूदा धोर्तियाशी पर भरोसा बनाए रखते हैं या खुद मैदान में उतरकर इस राजनैतिक जुए को खेलने का साहस दिखाते हैं।

नामांकन की प्रक्रिया लोकतंत्र के भव्य भवन की तरह पहली ईंट है, जिस पर पूरे चुनाव की शुचित्वा, विश्वसनीयता और पारदर्शिता टिकी होती है और उससे प्रदेश जैसे राज्य में, जहां की राजनीति जाति, धर्म, क्षेत्रीयता, बाहुबल और धनबल के अत्यधिक जटिल ताने-बाने से बुनी गई है, वहां नामांकन को निर्विज असुर निष्पन्न बनाना एक युगांतकारी कार्य है। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच का %अयोध्या नामांकन चैलेंज% यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश का आगामी चुनाव किसी भी सामान्य चुनाव से अलग, एक वैचारिक और व्यक्तिगत प्रतियोगिता लड़ाई बनने जा रहा है। चुनौतियाँ चाहे राजनैतिक दलों के भीतर टिकटों को लेकर मंचे घमासान की हलकों कलेक्ट्रेट के बाहर कानून-व्यवस्था की हों, या फिर दोनों शीर्ष नेताओं के बीच आगमने-सामने के मुकाबले की हों—इन सबका समाधान केवल और केवल सख्त प्रशासनिक इच्छाशक्ति, चुनाव आयोग की निष्पक्षता और राजनैतिक दलों की लोकतांत्रिक परिपक्वता में ही निहित है। उत्तर प्रदेश की जागरूक जनता नामांकन के इस शोर-शराबे, रैलियों के शक्ति प्रदर्शन और शीर्ष नेताओं की इस राजनैतिक जंग के बीच हर उम्मीदवार के हलचल-चल, उसके आचरण और उसकी पार्टी की नीति का बहुत सूक्ष्मता से मूल्यांकन कर रही है और आने वाले महीनों में यह देखा अत्यंत दिलचस्प होगा कि देश का यह सबसे बड़ा राजनैतिक सूबा इन चुनौतियों से पार पाकर किस तरह एक नए राजनैतिक भविष्य की इबारत लिखता है और क्या %अयोध्या% वास्तव में इस महामुकाबले का मुख्य केंद्र बिंदु बनती है।

भारत के आंतरिक मामलों में 'संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय' का रोना-धोना अनुचित

ऋतुपर्ण दत्ते

भारत के विरुद्ध भ्रम फैलाने वाले विशेषी संगठनों को यह अधिकार कतई नहीं है कि वे विदेश में बैठकर भाग में हो रहे आन्दोलन पर टिप्पणी करें और बिना मांगें सलाह दें। कम से कम उन संगठनों को तो बिल्कुल भी नहीं, जिनकी कार्यप्रणाली और मंशा प्रायः संदिग्ध और पूरी तरह से एकतरफा होती है। इससे भी बड़ी और समझने वाली बात यह है कि ऐसे संगठन जो तो भारत के बारे में पूरी तरह से जानते हैं और न ही उनको भारत को लेकर कुछ जानकारी होती है। हद तो तब हो जाती है जब वे बिना जांचे-परखे, व्यवस्था पर उंगली उठाने लगते हैं। निश्चित रूप से इनकी मंशा अंतरीष्टीय मंच पर भारत की छवि को खराब दिखाने की होती है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय यानी ओ.एच.सी.एच.आर. की टिप्पणी इन दिनों बेहद चर्चा में है। इसने हाल ही में दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इसतीफे की मांग पर प्रदर्शनकारियों के सामूहिक गिरफ्तारी और उनको हिरासत पर ड़्क़चता जताई और बयान जारी किए। 'काँकरोच जनता पार्टी' के नेतृत्व में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारियों, वकीलों, पत्रकारों और सचिव सोसायटी के लोगों को हिरासत में लिए जाने की विदेश में बैठे संगठन की पूर्वाग्रहों से ग्रसित ड़्क़चताएं यकीनन भारत के अन्दरूनी मामलों में दखल से कम नहीं हैं। ओ.एच.सी.एच.आर. ने विरोध-प्रदर्शनों से पहले और प्रदर्शन के दौरान बड़े पैमाने पर हुई गिरफ्तारियों पर दिखावटी आंसू भी बहाए, जो गलत है। संयुक्त

मानवाधिकारों का प्रवर्धन था मीनो अल खोतान ने एक बयान में कहा कि था कि हम भारतीय अधिकारियों को नुकसान चारों तरफ से यह बात सुनिश्चित करें कि शांतिपूर्ण सभा का अधिकार सभी को है जिसका पूरी तरह से सम्मान और पालन किया जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इस मामले पर दोनों पक्षों को समर्थक संवाद में शामिल होना चाहिए। जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र में भारतीय दूतावास ने संयुक्त राष्ट्र की चिन्ताओं को गलत बताकर इस अपील को पूरी तरह से न केवल खारिज कर दिया, बल्कि इस भारत के आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप और दखल बानाया। भारत ने इस पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि यानी ओ.एच.सी.एच.आर. को नियुक्त और गैर-न्यायानुसंगतता के अनुरूप, अन्य देशों में हो रहे हैं। इसमें के विरोध प्रदर्शनों की भी ध्यान देना चाहिए। इसने इस बात पर जोर दिया गया कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां शांतिपूर्ण सभा का अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त है और सभा के संस्थाओं, स्वतंत्र न्यायपालिका और स्वतंत्र मीडिया द्वारा संरक्षित है। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि हर लोकतंत्र को तरह भारतीय नागरिक, सार्वजनिक व्यवस्था के हित में उचित प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए धरना, प्रदर्शनों के ऐसे अधिकार का प्रयोग करते हैं। इसमें यह भी कहा गया कि अधिकारी कानून के अनुसार कार्य करते हैं और किसी भी शिकायत के निवारण के लिए न्यायालय सबके लिए उपलब्ध है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि जिस तरह की टिप्पणी की गई है उससे दोहरे मापदण्ड के तहत बहुपक्षीय संस्थाओं पर वैश्वक विश्वास कमजोर होता है।

जंतर मंतर प्रदर्शन वाली एफआईआर वापस लेने का गलत असर पड़ा

नीरज कुमार दुबे

दिखीं को सड़कों पर इन दिनों जो कुछ दिखाई दे रहा है, उसमें केवल प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने-सामने नहीं हैं। उनके बीच अब मोबाइल कैमरा भी खड़ा है, सोशल मीडिया भी खड़ा है और कुछ सेकंड में किसी घटना को देशभर में पहुंचा देने वाली तकनीक भी खड़ी है। शायद इसीलिए दिल्ली पुलिस के लिए आज किसी प्रदर्शन को नियंत्रित करना केवल बैरिकेड लगाने, भीड़ को रोकने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने का मामला नहीं रह गया है। पुलिस को कानून लागू भी करना है, स्वयं को उकसावे से बचना भी है और साथ-साथ यह सुनिश्चित भी करना है कि अगले कुछ सेकंड में उसकी कोई प्रतिक्रिया काट-छोटकर वायरल वीडियो न बन जाए।

दा अक्टूबर से नई दिल्ली क्षेत्र में शुरू
हए प्रदर्शनों ने कुछ ही दिनों में पुलिस के
सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है।
अलग-अलग राजनीतिक दलों, छात्र
संघटना, कार्यकर्ताओं और दूसरे समूहों के
प्रदर्शन तथा प्रतिबंधित क्षेत्रों की तरफ बढ़ने
को कौशलों के कारण पुलिस को लगातार
अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही है। केवल
एक स्थान पर खड़ी भीड़ के बजाय अलग-
अलग दिशाओं में आगे बढ़ते समूहों को
संभालना पुलिस के लिए नई चुनौती बन
गया है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच
एक असहज सवाल भी उठता है।

सवाल यह है कि क्या जुलाई में जंतर- एफआईआर



तर के प्रदर्शन से जुड़े मामलों में प्राथमिकी निरस्त किए जाने के चलते ही प्रदर्शनकारियों के बीच यह संदेश गया कि पुलिस के साथ टकराव का कानूनी परिणाम गंभीर नहीं होगा? क्या इसी कारण प्रदर्शनकारियों के मन में पुलिस का डर कम हो गया है? क्या इसी कारण कुछ लोग अब पुलिसकर्मियों से आक्रामक भाषा में बात करने, उन्हें चुनौती देने, धक्का-मुक्की करने या जानबूझकर उसकाने का जोखिम अधिक आसानी से उठा रहे हैं? हम आपको याद दिला दें कि जुलाई में हुए प्रदर्शनों के बाद दिल्ली पुलिस ने कई मामले दर्ज किए थे। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा। सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिकियों को निरस्त कर दिया। साथ ही अदालती आदेश में यह भी कहा गया था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन में केवल भागीदारी अपने आप में अपराध नहीं मानी जा सकती। ऐसे में जब महिला पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी और शारीरिक खींचतान के मामले सामने आ रहे हैं और पुरुष पुलिसकर्मियों पर दुर्व्यवहार के झूठे आरोप त लगाये जा रहे हैं तब यह स्वाल प्रमुखता से उठता है कि क्या एफआईआर निरस्त कर प्रदर्शनकारियों को

सुधरने का जो मौका दिया गया था उसका उन्होंने गलत फायदा उठाया ?

दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस भी आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में तकनीक के सहारे अपना बचाव कर रही है। नई दिल्ली क्षेत्र में तैनात पुलिसकर्मियों की वर्दी पर बाँड़ी-वॉर्न कैमरे लगाए गए हैं। संभव मार्ग पर प्रदर्शन से निपटने के लिए तैयार पुलिसकर्मियों की वर्दी पर ये छोटे कैमरे साफ दिखाई दे रहे हैं। पुलिस की रणनीति में सार्वजनिक उद्घोषणा के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल बढ़ाया गया है। और कई पुलिसकर्मी डंडों के बिना तैनात दिखाई दिए। देखा जाये तो बाँड़ीकैम का अर्थ केवल पुलिस को आरोपों से बचना नहीं है। यदि कोई पुलिसकर्मी सीमा पार करता है तो वही कैमरा उसके खिलाफ भी प्रमाण बन सकता है। यदि कोई प्रदर्शनकारी पुलिस को जानबूझकर उकसाता है, बैरिकेड तोड़ता है, हमला करता है या बाद में घटनाक्रम का अधूरा वीडियो प्रस्तुत करता है तो पुलिस के पास पूरी घटना का अपना दृश्य रिकॉर्ड मौजूद रहेगा।

इसके अलावा, सुरक्षा व्यवस्था में दूसरा बड़ा परिवर्तन बहुस्तरीय बैरिकेडिंग है। प्रदर्शनकारियों को प्रतिबंधित क्षेत्रों की ओर बढ़ने से रोकने के लिए कई स्टारों पर अवरोध लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जगुलई की घटनाओं के बाद दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। ताजा प्रदर्शनों से पहले उन स्थानों तक की

पहचान को गई जहाँ टूटा हुआ फुटपाथ,
पत्थर अथवा दीवार का हिस्सा तनाव बढ़ने
पर हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा
सकता है। जुलाई के अनुभवों के बाद
सुरक्षा व्यवस्था को इस तरह समीक्षा बताती
है कि अब भीड़ जब भी केवल पुलिस
बल की संख्या नहीं, बल्कि प्रदर्शन-स्थल
के भौतिक वातावरण को भी सुरक्षा का
हिस्सा माना जा रहा है।

एक और समस्या सांशल माओवा की है। पुलिसकर्मी के चेहरे के बिल्कुल सामने कैमरा रख देना, लगातार सवाल करना, नारे लगाना अथवा ऐसी परिस्थिति बनाना जिसमें उससे कोई तीखी प्रतिक्रिया निकल जाए, ऐसे माहौल में पुलिसकर्मी के कुछ सेकंड के नियंत्रण खोने का परिणाम लाखों लोगों तक पहुंचने वाला वीडियो हो सकता है। इसीलिए नई पुलिस रणनीति में आत्मसंयम स्वयं एक सुरक्षा उपकरण बन गया है। इस चुनौती को गंभीरता तब और बढ़ जाती है जब तकनीक के जरिये फर्जी दृश्य भी बनाए जाने लगे। दिल्ली पुलिस ने हाल में एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसने एक एआई की मदद से ऐसा वीडियो बनाया जिसमें एक पुलिसकर्मी को महिला के साथ दुर्व्यवहार करते दिखाया गया था।

बहरहाल, इसमें कोई दो राय नहीं कि दिल्ली पुलिस के सामने इस समय बेहद कठिन चुनौती है। उसे प्रदर्शन के लोकतांत्रिक अधिकार की रक्षा करनी है। उसे प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा करनी है। अपने जवानों विशेषकर महिला पुलिसकर्मीयों की सुरक्षा करनी है।

ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਕਾ ਟਾਂਡਵ: ਵਦੀ ਬਨੀ ਟਰਾਸਦੀ

ललित गर्ग

पंजाब की धरती कभी शौर्य, पराक्रम, मेहनत, उद्यमशीलता और जीवतवा के लिए जानी जाती थी। इस मिट्टी के नौवांनों ने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी और खेतों में पसीना बहाव कर देश का अन्न भंडार भरा। लेकिन आज उसी पंजाब व महान नशे के बढ़ते कारोबार, युवाओं की बर्बादी और इतना माफिया के बढ़ते प्रभाव से जुड़ती जा रही है। यहाँ केवल एक राज्य को सामाजिक त्रासदी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, शासन-व्यवस्था और राजनीतिक इच्छाशक्ति का भी गंभीर परीक्षा है। जिस पंजाब के युवाओं के हाथों में कलश, तलवार, हल और तिरंगा शोभा देते हैं, वहाँ आज नशे के अनेक हाथों को बेबस और अनेक परिवारों को बदवासा कर दिया है। विरंडना देखिक जिन नशे के कारोबार में अंकुश लगाने की जिम्मेदारी जिन पुलिसकर्मियों की है यदि उन्हीं के घर से करोड़ों रुपये की हेरोइन बरामद हो तो किसी खर्ब सामने आती है, तो यह व्यवस्था के लिए खर्च की घंटी है। पंजाब में एक पुलिस कांस्टेबल के घर में कथित तौर पर 40 करोड़ रुपये की हेरोइन बरामद होने पर मामला इसी संधि के अंतर् में करती है। यह व्यवस्था माफिया एक अपराधिक प्रकरण बल, बल्कि उस व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न है, जिसमें अपराध रोकने के लिए नियुक्त व्यक्ति ही कथित तौर पर अपराध के संदेह के लिए न आ जा जाए। यह तो वही स्थिति यह कि 'बाढ़ ही खेत व नष्ट खाने लगे', तो फसल की रखवाली कौन करेगा? जिन पुलिस के कंधों पर नशा तस्करों को पकड़ने का दायित्व है, यदि उसी व्यवस्था के धात एसे तत्व स्वयं लगे, और अगर नागरिक का भरोसा धागमना स्वाभाविक है। इस मामले में निष्पक्ष जांच, दोषियों की पकड़ना और कानूनी कार्रवाई जरूरी है। किसी व्यक्ति को केवल आरोप के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन व्यक्ति की आड़ में अपराध करने वालों किसी भी व्यक्ति को कानून से बचने का अवसर भी नहीं मिलना चाहिए।

पंजाब में नशे का कारोबार अब गलियों, गांवों और



कह्यो तब अपनी जड़ें फैला चुका है। कभी नशे की समस्या को सीमावर्ती क्षेत्रों या शहरी युवाओं तक सीमित माना जाता था, लेकिन आज सिंथेटिक ड्रग्स सहित विभिन्न मादक पदार्थों की उपलब्धता ने संकेत को और व्यापक बना दिया है। युवा पीढ़ी का एक हिस्सा नशे की गिरफ्त में आकर अपना स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और भविष्य गंवा रहा है। कहीं माँ की गोद सूनी हो रही है, कहीं वृद्ध पिता के बुढ़ापे का सहारा निरुह रहा है और कहीं परिवार का कामाउ सदस्य नशे की लत के कारण स्वयं अपने परिवारों पर बोझ बन रहा है। घर का चिराग ही घर में अंधेरा कर देता है, इससे बड़ी टोड़बना क्या होगी! नशे की लत केवल व्यक्ति को नहीं तोड़ती, बल्कि पूरे परिवार और सामाजिक ताने-बाने को भीतर तक खोखला कर देती है। इस संदर्भ की गंभीरता सरकारी आंकड़ों और पुलिस की कार्रवाइयों से भी समझी जा सकती है। उपलब्ध विवरणों के अनुसार सड़क महलों में पंजाब में 15,524 तस्करो को गिरफ्तार किया, जिनमें 153 बड़े ऑपरेटर शामिल थे। इस दौरान 790 किलोग्राम हेरोइन, 860 किलोग्राम अफीम और अन्य मादक पदार्थों के साथ 13 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जब्त की गई तथा नशे के कारोबार से जुड़ी 208 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति पर कार्रवाई की गई। ये आंकड़े कार्रवाई के पैमाने की अवश्य दर्शाते हैं, लेकिन साथ ही यह सवाल भी उठते हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में नशीली पदार्थ आखिर राज्य में पहुँच कैसे रहे हैं? इतनी गिरफ्तारियों और जब्त के बावजूद यदि नशे की उपलब्धता और लत पर निर्णायक अंकुश नहीं लग रहा, तो स्पष्ट है कि समस्या की जड़ें गहरी हैं। मर्ज बढ़ता गया, ज्यों-ज्यों दवा

की' जैसी स्थिति से बचने के लिए गिरफ्तारियों की संख्या से आगे बढ़कर नशे की आपूर्ति, वित्तीय नेटवर्क और राजनीतिक संरक्षण की पड़ताल करनी होगी।

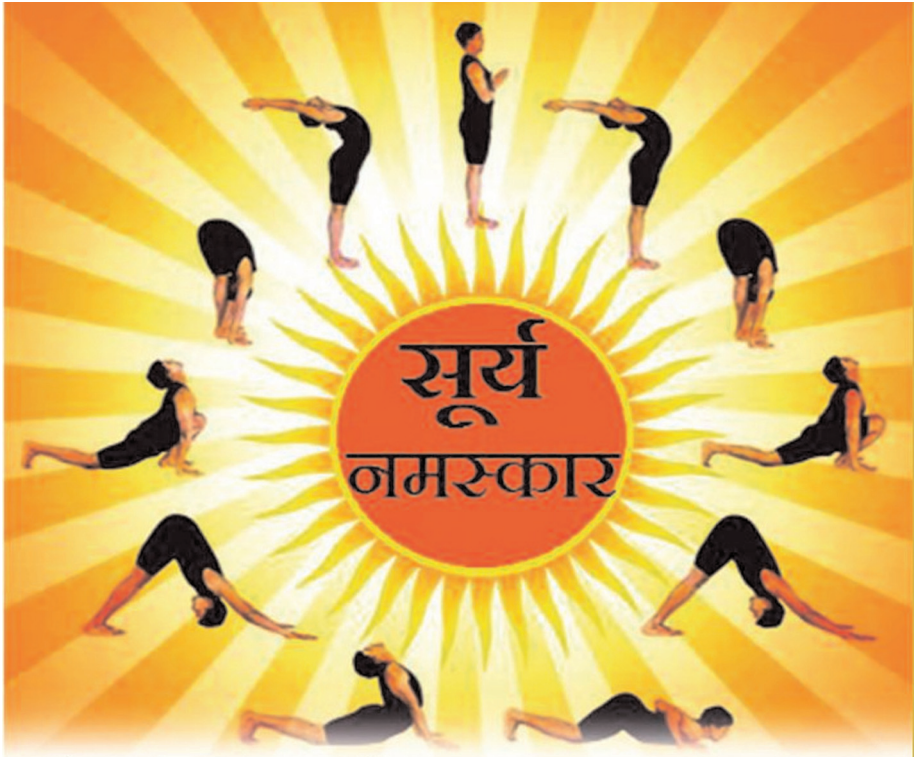
पाकिस्तान से लगा पंजाब की लगभग 553 किलोमीटर लंबी सीमा इस चुनौती को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ती है। ड्रोन के माध्यम से नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी की आशंकाएं सीमा प्रबंधन को और जटिल बनाती हैं। वर्ष 2026 में अब तक पंजाब की सीमा से 183 ड्रोन जब्त किए जाने का उल्लेख इस खतरे की गंभीरता को रेखांकित करिए हैं। सीमा पार से संचालित तस्करी के नेटवर्क पर प्रहार करना आवश्यक है, लेकिन सारी जिम्मेदारी बाहरी ताकतों पर डालकर राज्य के भीतर की कमजोरियों से आंखें नहीं मूंदी जा सकती हैं। यदि स्थानीय तस्कर, संगठित गिरोह और भ्रष्ट तंत्र मिलकर काम कर रहे हों, तो सीमा पर कड़ी निगरानी के साथ-साथ भीतर भी कठोर कार्रवाई करनी होगी। "दूध का दूध और पानी का पानी" करने वाली जांच ही बड़ा सक्ती है कि इस काले कारोबार में कौन मोहरा है, कौन खिलाड़ी और कौन पर्दे के पीछे बैठा सूत्रधार। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने नशामुक्ति और तस्करो के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर अनेक दावे किए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये दावे जमीन पर उतना परिवर्तन ला पाए हैं, जिसकी अपेक्षा पंजाब की जनता ने की थी? सता में आने से पहले नशे के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई के वादे करना आसान है, लेकिन उस लड़ाई को परिणाम तक पहुंचाना राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक ईमानदारी और निरंतर जवाबदेही मांगता है। यदि नशे की उपलब्धता बनी हुई है, युवा लगातार इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं और तस्करी के नेटवर्क बार-बार सक्रिय हो जाते हैं, तो सरकार की रणनीति और उसके क्रियान्वयन पर सवाल उठाना स्वाभाविक है। केवल छापेमारी, गिरफ्तारी और घोषणाओं से नशामुक्त पंजाब का सपना साकार नहीं होगा। सरकार की सफलता का वास्तविक पैमाना यह होना चाहिए कि नशे का आपूर्ति कितनी घटी, कितने युवा उपचार के बाद सामान्य जीवन में लौटे और बड़े तस्करो तथा उनके संरक्षकों के विरुद्ध कितनी प्रभावी कार्रवाई हुई।

फ्रांस में कुछ ठीक नहीं हो रहा

मुजतबा रहमान

फ्रांसीसी भाषा में एक मुहावरा है: उन एग्जेनेज, यानी एक ऐसा दुष्कर्म, जो लगातार गहरा होता जाता है। फ्रांस अभी इसी स्थिति में फंसा है। यहाँ कई संकट लंबे समय से पनप रहे हैं; और अब हालात ऐसे हैं कि हर संकट दूसरे संकट को और तेजी से बढ़ाने का खतरा पैदा कर रहा है। वर्तमान सरकार के कलह पहला संकट सर्वश्रेष्ठ में मिल रहे संकेत हैं। तटस्थता है कि अगले वसंत में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में धुर दक्षिणपंथी गुट सत्ता में आ सकता है। दूसरा संकट वित्तीय कृपब्रंभन का है। फ्रांस का सार्वजनिक कर्ज रिकॉर्ड 40 खरब डॉलर तक पहुँच गया है, और सरकार के लिए नया कर्ज लेना कहीं अधिक महंगा हो गया है। तीसरा संकट युवाओं की नाराजगी का है। जर्जर स्कूलों और सीमित अवसरों के खिलाफ विरोध जताते हुए, फ्रांसीसी छात्रों ने पिछले कुछ हफ्तों में देश के लगभग आधे हाई स्कूलों को बंद कर दिया है। छात्रों के प्रदर्शन देश के हर हिस्से में—बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों के सरकारी स्कूलों तक फैल गए हैं। वे लंबी पढ़ाई के घंटों, बड़ी कक्षाओं, शिक्षकों की बार-बार अनुपस्थिति और जर्जर होती स्कूलों की इमारतों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। हालाँकि, संकेत भी साफ तौर पर मिल रहे हैं कि ओटोलनकारियों को ग्लोबल वार्मिंग और नौकरियों पर एआई के खतरे के अलावा, दक्षिणपंथी विचारधारा के उभार की भी चिंता है। फ्रांसीसी सरकार शिक्षा पर काफी खर्च करती है—हर साल लगभग 100 अरब डॉलर, जो कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 5.1 प्रतिशत है। यह यूरोपीय संघ के औसत से भी अधिक है। लेकिन, इस रकम का एक-चौथाई से ज्यादा हिस्सा रिटायर हो चुके शिक्षकों की पेंशन देते में खर्च होता है। सरकारी खर्च का लगभग एक-चौथाई हिस्सा पेंशन में चला जाता है; और एक और चौथाई स्वास्थ्य सामाजिक सेवाओं पर खर्च होता है, जिसमें स्वास्थ्य सेवा से लेकर

ग्रेनेजोगारी भूते तक शामिल हैं। पिछले 52 वर्षों में फ्रांस को किसी भी सरकार ने अपना बजट संतुलित नहीं किया है। इसके बावजूद, फ्रांस पर कर्ज का बोझा (जो उसके जीडीपी का 119 प्रतिशत है) अमेरिका सहित कई अन्य देशों की तुलना में कम है। 2019 में, राष्ट्रपति मैक्रॉन वार्षिक घाटे को यूरोपीय संघ (ईयू) के तीन प्रतिशत जीडीपी वाले लक्ष्य के दायरे में लाने में सफल रहे थे। फिर महामारी आ गई। लॉकडाउन के दौरान फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था को बचाए रखने की कोशिश के चलते 2020 में घाटा बढ़कर जीडीपी का 9.2% हो गया। एक साल में कुल कर्ज 335 अब्ज डॉलर पड़ गया। फिर, 2021 में रुस द्वारा यूक्रेन पर हमला किए जाने के बाद, उर्जा की बढ़ती कीमतों से फ्रांस को बचाने के लिए सरकार ने 95 अब्ज डॉलर और खर्च किया। इसके बाद, मैक्रॉन का नियंत्रण स्वप्न हो गया। 2022 में वह फिर से चुने गए, लेकिन नेशनल असेंबली में बहुमत हासिल करने में नाकाम रहे। 2023 में उन्होंने पेंशन व्यवस्था में कुछ बदलाव किए, जिसके तहत सेवानिविष्टि की उम्र को 62 से बढ़ाकर 64 साल कर दिया गया। लेकिन, फ्रांस के 70% से अधिक लोग इससे सहमत नहीं थे, और कुछ लोगों ने तो हिंसक विरोध भी किया। इसके जवाब में, मैक्रॉन ने 2024 में जल्दबाजी में चुनाव कराने का एक गलत फैसला लिया, जिससे उनके मध्यमगीरा गुब्बहन की ताकत को हारा हो गई। तब से, दो प्रधानमंत्रियों ने खर्च को कम करने के लिए कुछ उपाय सुझाए हैं। लेकिन, नेशनल असेंबली में वामपंथी और धुर-दक्षिणपंथी सांसदों के बहुमत ने उन दोनों को ही सत्ता से अबाहर कर दिया। नतीजा यह हुआ है कि देश में एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है। इस गड़बड़ी के लिए कुछ हद तक मैक्रॉन स्वयं जिम्दार हैं। विश्वभूषण जैसे धुर-वामपंथी गृह से लेकर सीरी ले पेन की 'नेशनल रैली' जैसे धुर-दक्षिणपंथी गृत तक शामिल हैं।



रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है सूर्य नमस्कार

दिन की अच्छी शुरुआत करने के लिए सूर्य नमस्कार सबसे अच्छा व्यायाम है। जिस प्रकार 12 राशियां, 12 महीने होते हैं, उसी प्रकार सूर्य नमस्कार भी 12 स्थितियों से मिलकर बना है। कोविड महामारी के समय में आप सूर्य नमस्कार को अपना कर अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं-

- सूर्य नमस्कार का अभ्यास इन 12 स्थितियों में किया जाता है, आइए जानें-
- दोनों हाथों को जोड़कर सीधे खड़े हों। नेत्र बंद करें। ध्यान 'आज्ञा चक्र' पर केंद्रित करके 'सूर्य भगवान' का आह्वान 'ॐ मित्राय नमः' मंत्र के द्वारा करें।
- श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कानों से सटाते हुए ऊपर की ओर तानें तथा भुजाओं और गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं। ध्यान को गर्दन के पीछे 'विशुद्धि चक्र' पर केन्द्रित करें।
- तीसरी स्थिति में श्वास को धीरे-धीरे बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुकाएं। हाथ गर्दन के साथ, कानों से सटे हुए नीचे जाकर पैरों के दाएं-बाएं पृथ्वी का स्पर्श करें। घुटने सीधे रहें। माथा घुटनों का स्पर्श करता हुआ ध्यान नाभि के पीछे 'मणिपूरक चक्र' पर केन्द्रित करते हुए कुछ क्षण इसी स्थिति में रुकें। कमर एवं रीढ़ के दोष वाले साधक न करें।
- इसी स्थिति में श्वास को भरते हुए बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं। छाती को खींचकर आगे की ओर तानें। गर्दन को अधिक पीछे की ओर झुकाएं। टांग तनी हुई सीधी पीछे की ओर खिंचाव और पैर का पंजा खड़ा हुआ। इस स्थिति में कुछ समय रुकें। ध्यान को 'स्वाधिष्ठान' अथवा 'विशुद्धि चक्र' पर ले जाएं। मुखाकृति सामान्य रखें।

मेडिटेशन को करें अपने रूटीन में शामिल और पाएं बेहतरीन फायदे

- मेडिटेशन को ही ध्यान लगाना कहते हैं, इसे दिनचर्या का हिस्सा बनाकर रोजाना करने से कई फायदे होते हैं। अगर अभी तक आपने मेडिटेशन को अपने रूटीन में शामिल नहीं किया है तो, ये 13 फायदे जानने के बाद आप कल से ही इसे अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेंगे -
- मेडिटेशन, मन अशांत रहने पर उसके निष्क्रिय पड़े हुए भागों को उपयोग में लाने योग्य बनाता है।
 - अनुभव की क्षमता को सूक्ष्म करने की एक प्रक्रिया है ध्यान।
 - दि आपको भूलने की आदत है तो ध्यान आपके लिए बहुत उपयोगी है।
 - गुस्सेल प्रवृत्ति के लोगों का मन शांत करने में कारगर है भावातीत ध्यान।
 - निर्णय न ले पाने वाले भी इसे अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हैं।
 - हृदयरोग की रोकथाम



लाइफस्टाइल बदल डाली तो ऐसे बड़ेगी इम्युनिटी



इम्युनिटी कमजोर होने में खराब जीवनशैली का बड़ा हाथ है। यह एक सर्वमान्य सत्य है कि शरीर पर बाहरी माइक्रोऑर्गेनिज्म के होने वाले हमलों के खिलाफ इम्यून सिस्टम पहली डिफेंस लाइन मानी जाती है। जितनी तगड़ी इम्युनिटी होगी उतने ही बीमारी पकड़ने के अवसर क्षीण होते जाएंगे। खराब जीवनशैली से इम्यून सिस्टम की डिफेंस में छेद होने लगता है।

खराब जीवनशैली

यदि आपके पास टीक से खाना खाने और भरपूर नींद लेने का वक़्त नहीं हो तो समझ लें कि आपकी जीवनशैली खराब है जो आपके इम्यून सिस्टम को तेजी से कमजोर कर रही है। यह टीक है कि आधुनिक जीवनशैली में वर्क प्रेशर इतना अधिक है कि उसका शरीर पर खराब असर पड़ रहा है लेकिन प्रेशर रहने के बावजूद भी स्वस्थ रहने के लिए प्रयत्न किया जा सकता है।

कब हुई थीं सालाना जांचे?

30 साल की उम्र हो जाने के बाद शरीर की नियमित जांचें कराना बेहद जरूरी है। इन दिनों अत्यधिक तनाव झेलने के कारण कम उम्र में ही हाई ब्लड प्रेशर अथवा शुगर की बीमारियां जड़ पकड़ लेती हैं। यह देखा गया है कि शुरुआती जांचों में ही कई बार लंबी बीमारियों की जड़ पकड़ में आ जाती है।

टाइम निकालें

खुद के लिए समय निकालें। यदि काम के घंटे फिक्स नहीं हैं तो वर्क स्टेशन की ही वर्कआउट के लिए सेट कर लें। काम के दौरान थोड़ी-थोड़ी देर में ब्रेक लेते रहें और शारीरिक गतिविधियां बढ़ा दें। मसलन आप स्पोर्ट्स रनिंग कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, वाशरूम तक तेज गति से जाकर वापस आ सकते हैं। वर्क स्टेशन एक्सरसाइज के बारे में जानने के लिए कई वेबसाइट्स हैं जो कई तरह के सॉल्युशन्स उपलब्ध कराती हैं।

पानी कब पिया था?

क्या आपको याद कि अंतिम बार आपने पानी कब पिया था? पानी न सिर्फ हाईड्रेट रखता है बल्कि हाजमा और किडनी दोनों को तंदुरुस्त रखता है। इम्यून सिस्टम टीक से काम करता रहे इसके लिए जरूरी है कि हाजमा टीक रहे। मेटैबॉलिक सिस्टम के बिगड़ते ही शरीर का हर अवयव और उसकी कार्यप्रणाली प्रभावित होती है।

ये बदलाव लाएं जीवनशैली में

लाइफस्टाइल को दुरुस्त कर लेना आपके लिए बिल्कुल आसान है लेकिन इसके लिए दृढ़ इच्छाशक्ति की जरूरत है। आपको केवल ठान लेना है बाकि सभी चीजें अपने आप टीक होने लगती हैं। आप इतना तो कर ही सकते हैं कि सुबह जब भी आप उठते हैं, एक गिलास कुनकुना नींबू पानी पीकर दिन की शुरुआत कर सकते हैं। यदि आप रोज देर से उठ रहे हैं तो काम के घंटों के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। नींबू पानी के साथ ताजे आंवले का रस मिल सके तो पी लें नहीं तो बाजार से आंवले के रस का पैक भी खरीद कर रख सकते हैं। संतरे का रस अथवा आंवले के रस से विटामिन सी का तगड़ा डोज सुबह उठते ही मिल जाए तो दिन की अच्छी शुरुआत मानी जा सकती है। अपने भोजन में अदरक और हल्दी को विशेष रूप से शामिल करने का आग्रह करें। इससे असमय सोने के कारण होने वाली एसिडिटी एवं जलन से राहत मिल सकती है।

गोल्डन मिल्क

रात को सोते समय हल्दी मिला हुआ दूध जरूर पिएं। जो लोग रात को जागते रहकर काम करते हैं उन्हें यह दूध खासतौर पर पीना चाहिए क्योंकि इससे उन्हें जागने के कारण होने वाली समस्याओं से निजात पाने में मदद मिलती है।



जब भी हमें छोटी-मोटी सेहत समस्या, हल्का सा दर्द व घाव आदि होता है तो हमारा शरीर उसे अपने आप ठीक करने में भी सक्षम होता है। लेकिन कई लोग जरा सी भी परेशानी होने पर अत्यधिक एंटीबायोटिक का सेवन करते हैं। अगर आप भी उन्हीं में से है तो आइए, आपको बताते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर होने से बचाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए

- एंटीबायोटिक - हममें से कई लोगों की आदत होती है, एंटीबायोटिक्स दवाओं का अत्यधिक सेवन करना। लेकिन गैरजरूरी समय पर इनका सेवन करने से आपकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो सकती है। अत्यधिक जरूरत के समय ही एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन करें।
- औषधियां - जब भी आप वायरल या शारीरिक दर्द महसूस करें, ऐसी आयुर्वेदिक या घरेलू औषधि अपने साथ रखें जो प्रतिरोधकता बनाए रखती हैं।
- नींद - पर्याप्त नींद न होना आपके दिमाग और शरीर को बेवजह थकावट देता है और आपकी प्रतिरोधकता भी कम होती है। हर दिन 8 घंटे की नींद आपको स्वस्थ और खुशगवार रखने में सहायक है।
- शुगर - शर्करा खाने से मनाही नहीं है, लेकिन अतिरिक्त शर्करा से भरे खाद्य पदार्थ जैसे सोडा, एनर्जी ड्रिंक, जूस व अन्य पदार्थों से दूरी बनाएं। यह आपकी सेहत का पूरा हिसाब गड़बड़ कर देंगे, और प्रतिरोधकता में कमी भी।
- धूप है जरूरी - त्वचा को अगर धूप से बचाते हैं, तो विटामिन डी की कमी हो सकती है। बल्कि धूप लेना प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए फायदेमंद साबित होता है। इसलिए पर्याप्त धूप लेने का नियम बनाएं।
- जिक - जिक की पर्याप्त मात्रा का सेवन भी प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने का एक बेहतरीन विकल्प है। इसके लिए अलग से जिक की गोлияयां खाने के बजाए ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करें, जिनसे आपको नैचुरल जिक प्राप्त हो।
- पतेदार सब्जियां - पतेदार सब्जियां या फिर सलाद जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन खूब करें। इनसे प्राप्त होने वाले एंजाइम्स आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में इजाफा करते हैं और हर तरह का पोषण प्रदान करते हैं, जिसकी आपको जरूरत है।

गर्म पानी के साथ लहसुन के फायदे

खाने के स्वाद को बढ़ाने तथा सब्जी व दाल में तड़का लगाने में लहसुन का प्रयोग आप खूब करते हैं। लहसुन जहां भोजन के स्वाद को बढ़ाता है, वहीं इसमें मौजूद पौष्टिक तत्व हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने की ताकत भी देते हैं। लहसुन हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, जो हमारे शरीर को अंदर से मजबूत रखता है और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। वहीं अगर हम लहसुन को गर्म पानी के साथ लें तो यह हमारे शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचाता है और कई बीमारियों से निपटने की ताकत देता है।

कब्ज की समस्या से राहत

यदि आप कब्ज की समस्या से परेशान हैं तो इससे राहत पाने के लिए आप गर्म पानी के साथ कच्ची लहसुन का सेवन करें। यह पाचन क्रिया को सही रखने में मदद करता करेगा और कब्ज की समस्या दूर होगी।

एंटी बैक्टीरियल व एंटीवायरल से भरपूर

बदलते मौसम का असर आपकी सेहत पर पड़ता है, वहीं बारिश के दिनों में यदि आप गर्म पानी के साथ लहसुन का सेवन करते हैं तो इससे आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और कई बीमारियों का खतरा कम



पीएम मोदी दिसंबर में करेंगे कनाडा का दौरा



नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 11 और 12 दिसंबर को कनाडा की यात्रा करेंगे। ओटावा स्थित भारतीय उच्चायोग ने यह जानकारी दी। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भी बृहस्पतिवार सुबह कैलगरी के एक स्थानीय रेस्तरां में लोगों से बातचीत के दौरान मोदी की यात्रा की तारीख की पुष्टि की। कार्नी ने कहा कि उन्होंने अभी मोदी से बात की है और वह टोरंटो एवं ओटावा की यात्रा करेंगे। उन्होंने कहा, हम देखेंगे कि क्या इस यात्रा का दायरा बढ़ाया जा सकता है। ओटावा स्थित भारतीय उच्चायोग ने बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि मोदी 11 और 12 दिसंबर को कनाडा की यात्रा करेंगे। पोस्ट में कहा गया, प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ हाल में हुई बातचीत में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आई सकारात्मक गति को आगे बढ़ाने और व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा तथा दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में ठोस नतीजे हासिल करने की दिशा में काम करने पर सहमति जताई है।

कांग्रेस का अराजकता फैलाकर सत्ता हथियाने की साजिश



नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस के चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर चौंकाने वाला दावा किया है। लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस और उसके साथी चुनाव आयोग के खिलाफ युवाओं के विरोध प्रदर्शन का इस्तेमाल राजनीतिक अशांति फैलाने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वे बांग्लादेश की तरह भारत में भी सरकार बदलना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष युवाओं को अव्यवस्था की राजनीति का मोहरा बनाकर देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में जो घटनाक्रम हुआ है, उससे कई गंभीर सवाल उठते हैं। ऐसा लगता है कि कांग्रेस और उसके राजनीतिक साथी, सीधे और अपने जुड़े संगठनों के जरिए, युवाओं की एनर्जी को रचनात्मक कामों और देश बनाने में नहीं, बल्कि राजनीतिक टकराव और अव्यवस्था फैलाने के तरीकों में लगाने की कोशिश कर रहे हैं।

संजय राउत के आचरण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त



नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और उसके प्रमुख ज्ञानेश कुमार को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में गड़बड़ी के आरोपों वाली एक याचिका पर दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि शिवसेना-यूबीटी नेता संजय राउत को अपने आचरण के बारे में स्पष्टीकरण देना होगा। यह याचिका कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राउत सहित 12 अन्य विपक्षी नेताओं ने दायर की थी। कोर्ट ने कहा कि वह राउत की ओर से दायर इस याचिका को फिलहाल स्वीकार कर रहा है, लेकिन यह उनके स्पष्टीकरण देने की शर्त पर निर्भर करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने गुरुवार को कहा डब्ल्यूपी (सी) संख्या 1351/2026 (आइटम 25, जिसे गांधी ने दायर किया है) में, याचिकाकर्ता संख्या 6 (राउत) की ओर से दायर याचिका को फिलहाल स्वीकार किया जा रहा है, लेकिन उन्हें अपने आचरण के बारे में स्पष्टीकरण देना होगा।

दिमागी नक्सलियों और देशभक्तों के बीच खिंची लकीर



नई दिल्ली। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरन रीजीजू ने शुक्रवार को कहा कि “दिमागी नक्सलियों” और देशभक्त भारतीयों के बीच लड़ाई की लकीर खिंच गई है। रीजीजू ने लोगों से “देशद्रोहियों” को याद रखने का आह्वान भी किया। रीजीजू ने उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण द्वारा बृहस्पतिवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन में “सत्ता परिवर्तन” संबंधी टिप्पणी किए जाने के एक दिन बाद यह टिप्पणी की है। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “लड़ाई की लकीर खिंच गई है। यह दिमागी नक्सलियों और देशभक्त भारतीयों के बीच की लड़ाई है। यह भारत के संविधान में विश्वास रखने वालों और अराजकतावादियों के बीच की लड़ाई है।” रीजीजू ने एक अन्य पोस्ट में कहा, “प्रिय देशभक्त भारतीयों... याद रखिए, अपने दुश्मनों को एक बार माफ कर दीजिए, दोस्तों को दो बार, लेकिन देशद्रोहियों को कभी माफ मत कीजिए।”

मोदी के लिए एलन मस्क से सीधे भिड़ गए ओवैसी



हैदराबाद। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने से कभी पीछे नहीं हटे हैं। लेकिन जब दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर एलन मस्क ने भारत के राजनीतिक और व्यावसायिक फैसलों के पीछे के अधिकार पर सवाल उठाया, तो हैदराबाद के सांसद ने सरकार का विरोध करने और किसी विदेशी कारोबारी को देश के लिए शर्तें तय करने की बूट देने के बीच का फर्क स्पष्ट किया। उनका यह रुख कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रतिक्रिया से बिल्कुल अलग था; राहुल गांधी ने मस्क के आरोपों का फायदा उठाते हुए, भारत के शक्तिशाली उद्योगपतियों के साथ भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के संबंधों पर फिर से हमला बोला। यह विवाद तब शुरू हुआ जब स्पेसएक्स के मालिक और टेक्ला के सीईओ एलन मस्क ने सार्वजनिक रूप से शिकायत की कि उनकी सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिनक को भारत में कमर्शियल कामकाज शुरू करने की अनुमति मिलने में देरी हो रही है। लेकिन अब यह मामला राजनीतिक रंग ले चुका है।

मतदाता सूची से क्यों काटे गए नाम?

एसआईआर पर कांग्रेस के हर आरोपों का भाजपा देगी जवाब

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी अगले हफ्ते से एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने की तैयारी कर रही है। इसका मकसद कांग्रेस के उन दावों का जवाब देना है, जिन्हें भाजपा गुमराह करने वाले दावे बताती है। ये दावे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और भारत निर्वाचन आयोग से जुड़े हैं। इस प्रस्तावित अभियान के तहत, भाजपा जनता के सामने तथ्य रखेगी ताकि एसआईआरऔर निर्वाचन आयोग के कामकाज को लेकर विपक्ष की ओर से उठाए गए सवालों और आरोपों का जवाब दिया जा सके। पार्टी के सांसदों, विधायकों और अन्य वरिष्ठ नेताओं को यह जिम्मेदारी दी जा सकती है कि वे अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में लोगों तक इस अभियान को पहुंचाएं।

भाजपा के सूत्रों के अनुसार, पार्टी 24 पनों का एक विस्तृत दस्तावेज तैयार कर रही है, जिसमें विपक्ष की ओर से उठाए गए सवालों और लगाए गए आरोपों के जवाब शामिल हैं। उम्मीद है कि यह दस्तावेज पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए जनसंपर्क गतिविधियों के दौरान एक संदर्भ सामग्री (रेफरेंस मटेरियल) के रूप में काम आएगा।

इस अभियान को सोशल मीडिया और अन्य संचार माध्यमों के जरिए भी चलाया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके और इस मुद्दे



पर पार्टी का पक्ष रखा जा सके। विपक्ष के मौजूदा आरोपों का जवाब देने के साथ-साथ, बीजेपी उन घटनाओं को भी उजागर करने की योजना बना रही है, जिनमें उसका आरोप है कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए चुनाव आयोग और अन्य संस्थानों का दुरुपयोग किया था। पार्टी इन उदाहरणों का इस्तेमाल कांग्रेस की आलोचना का जवाब देने और जनता के सामने अपना पक्ष रखने के लिए करना चाहती है।

इस अभियान में देश भर के पार्टी नेताओं और संगठनात्मक इकाइयों के समन्वित प्रयास शामिल होंगे। इसमें सत्ता में रहते हुए चुनाव आयोग और अन्य संस्थानों का दुरुपयोग किया था। पार्टी इन उदाहरणों का इस्तेमाल कांग्रेस की आलोचना का जवाब देने और जनता के सामने अपना पक्ष रखने के लिए करना चाहती है।

कनॉट प्लेस में कारोबार बंद होने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

कहा- हमें उम्मीद है कि सभी लोग समझदारी से काम लेंगे

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि अगर कॉर्करोच जनता पार्टी की ओर से घोषित तिरंगा विरोध प्रदर्शन के कारण दिल्ली के कनॉट प्लेस को बंद करने से कारोबार का कोई गैर-कानूनी नुकसान होता है, तो कोर्ट अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करेगा।

याचिका को सूचीबद्ध करने के अनुरोध पर, मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने कहा कि अगर नई दिल्ली नगर निगम की ओर से लगाई गई पाबंदी जरूरत से ज्यादा (अनुचित) पाई जाती है, तो कोर्ट मुआवजे के लिए तय किए गए सिद्धांतों के अनुसार कार्रवाई करेगा।

अदालत दशहरा की छुट्टियों के बाद, 26/27 अक्टूबर को इस मामले को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गई। वकील जय अनंत देहादराय ने दिल्ली किराना कमिटी और दिल्ली आयरन एंड हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन द्वारा दायर एक याचिका का जिक्र किया। इसमें सेंट्रल पार्क में विरोध प्रदर्शन के आह्वान को लेकर चिंता जताई गई है। उनके अनुसार, इससे रोजाना 200 करोड़ रुपये का व्यापार बाधित होगा। उन्होंने बताया कि नई दिल्ली नगर निगम ने गुरुवार की रात एक नोटिस जारी करके उस जगह को बंद करने का आदेश दिया है।

इसके बाद बेंच ने बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट में पहले से ही इसी तरह के एक मामले की सुनवाई चल रही है। हालांकि, वकील ने दावा किया कि यह मामला अलग है। जस्टिस बागची ने कहा, यह अलग नहीं है। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। कोई विरोध प्रदर्शन करना चाहता है, कोई मृंगफली बेचना चाहता है, कोई कानून-व्यवस्था बनाए रखना चाहता है। ये सब एक-दूसरे से जुड़े हैं।



इसके बाद वकील ने कहा कि चूंकि त्योहारों का सीजन आने वाला है, इसलिए जगह घिरने से कारोबार को भारी नुकसान होगा। सीजेआई सूर्य कांत ने यह भी कहा कि व्यापार में रुकावट आने से कई परिवारों की आजीविका पर असर पड़ सकता है। सीजेआई सूर्य कांत ने कहा, हमें उम्मीद है कि सभी लोग समझदारी से काम लेंगे। हम जानते हैं कि छोटे दुकानदार जहाँ दिनों में अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं। हमें पता है कि पूरे परिवारों को किन मुश्किलों और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

इसके साथ ही जस्टिस बागजी ने कहा, अगर कारोबार का नुकसान होता है। हम यह पाते हैं कि आपके क्लाइंट्स के लिए यह गैर-कानूनी है, तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल टॉट अधिकार क्षेत्र के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे। जब वह स्थिति आएगी। तब उस पर विचार किया जाएगा।

जब वकील ने इस बात पर जोर दिया कि एनडीएमसी के नोटिस से सेंट्रल दिल्ली में पूरा कारोबार बंद हो जाएगा, तो जस्टिस बागजी ने फिर कहा, अगर हमें लगता है कि एनडीएमसी का आदेश जरूरत से ज्यादा सख्त पाबंदी है, तो जैसा कि हमने पहले ही कहा है इस कोर्ट के पास मुआवजा और सार्वजनिक कानून के तहत काफी अधिकार क्षेत्र मौजूद है। हम कार्रवाई करेंगे।

शेयर बाजार में रौनक

सेंसेक्स 413 अंक चढ़कर बंद

मुंबई। भारतीय शेयर बाजार में पिछले दो दिनों से जारी तेजी शुक्रवार को भी बरकरार रही। सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के शेयरों में हुई जोरदार लिवाली और मजबूत वैश्विक संकेतों के दम पर घरेलू बेंचमार्क सूचकांक लगातार दूसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुए। बीएसई का 30 शेयरों वाला प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 413.66 अंक की तेजी के साथ 74,729.27 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं, एनएसई इंडेक्स के दौरान बाजार में काफी उतार-चढ़ाव देखा गया। एक समय सेंसेक्स 463.17 अंक उछलकर 74,778.78 के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया था। गौरतलब है कि इससे पिछले कारोबारी सत्र यानी गुरुवार को भी बाजार में रिकॉर्ड तोड़ तेजी देखी गई थी, जब सेंसेक्स में 1,533 अंकों से ज्यादा का उछाल आया था। दो दिनों की इस लगातार रिकवरी से निवेशकों में भारी उत्साह है।

डेलॉयट ने बढ़ाया भारत की जीडीपी ग्रोथ अनुमान

नई दिल्ली। डेलॉयट इंडिया ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के 7.1 से 7.3 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। निजी निवेश में लगातार सुधार से मांग को अतिरिक्त समर्थन मिलने की उम्मीद है। बहुराष्ट्रीय पेशेवर सेवा कंपनी ने कहा कि हालांकि भू-राजनीतिक तनाव, ऊर्जा की कीमतों में उतार-चढ़ाव और व्यापार में व्यवधान आर्थिक वृद्धि की संभावनाओं के लिए जोखिम बने हुए हैं। डेलॉयट इंडिया की अर्थशास्त्री रुमकी मजूमदार ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक वृद्धि की घरेलू खर्च में मजबूती और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में लगातार निवेश से समर्थन मिला है। कारोबारों को अब बेहतर संपर्क सुविधा, मजबूत वित्तीय स्थिति और उत्पादन क्षमता का अधिक इस्तेमाल करने का लाभ मिल रहा है जिससे विस्तार की संभावना मजबूत हुई है।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौता जल्द से जल्द पूरा होने की उम्मीद



नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को उम्मीद जताई कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को वैश्विक व्यापार तथा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों के हित में जल्द से जल्द अंतिम रूप दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि हाल में भारतीय वाणिज्य मंत्री ने भी कहा है कि वे समझौते पर जल्द हस्ताक्षर होने की उम्मीद कर रहे हैं और ऐसा चाहते हैं। बातचीत जारी है। मुझे उम्मीद है कि वैश्विक व्यापार और दोनों सझेदारों, भारत तथा अमेरिका के बीच व्यापार के हित में इस समझौते को जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बृहस्पतिवार को कहा था कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप दे दिया गया है और उसके कानूनी मसौदे पर काम जारी है।

सेबी के नए सीएएस नियमों से ट्रेडर्स को राहत

नई दिल्ली। शेयर बाजार में कारोबारी सेशन के आखिरी हिस्से के ट्रेड और डेरिवेटिव्स सेटलमेंट से जुड़े नियम बदलने जा रहे हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने क्लोजिंग ऑक्शन सेशन यानी सीएएस का समय घटाकर 10 मिनट कर दिया है। इसके अलावा एकस्पायरी के दिन इंडेक्स और शेयर डेरिवेटिव्स का सेटलमेंट कैश मार्केट के आखिरी 30 मिनट के एक्वेज ट्रेडिंग ड्राइस के आधार पर होगा। इससे सेटलमेंट की कीमत को लेकर बनी अनिश्चितता कम होने की उम्मीद है। एनालिस्ट्स का मानना ​​है कि सेबी की ओर से इन बदलावों का फायदा स्टॉक एक्सचेंज के मुकाबले ब्रोकिंग कंपनियों को ज्यादा मिल सकता है। बता दें कि सीएएस के लिए सेबी की 20 हजार से ज्यादा मुझाव मिले थे।

स्टेल प्रमुख समाचार

भारत और वेस्टइंडीज के बीच अंतिम टी20 मैच आज

बेंगलुरु। भारत शनिवार को पांचवें और आखिरी टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में एक शानदार शुरुआत को जीत में बदलने की क्षमता और उनके गेंदबाजों की विपक्षी टीम को मैच पर हावी होने से रोकने की काबिलियत पर सबकी नजरें रहेंगी। वहीं वेस्टइंडीज की नजर सरीज जीतने पर होगी भारत को जीत के लिए आक्रामक क्षमता की धार तेज करनी होगी। सीरीज अभी 2–2 से बराबरी पर है, और हैदराबाद में खेले गए चौथे मैच ने भारत को सोचने पर मजबूर कर दिया है। वेस्टइंडीज की 24 रन से जीत सिर्फ यह नहीं दिखाती कि उन्होंने दूसरी टीम से अधिक रन बनाए, बल्कि यह भी बताती है कि आक्रामक क्रिकेट खेलने और लक्ष्य का पीछा करते हुए निरंत्रण खो देने के बीच कितना बारीक अंतर होता है।

भारत ने 248 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए बेहतरीन इरादे के साथ शुरुआत की और पहले चार ओवरों में बिना कोई विकेट खोए 60 रन बना लिए। संजू सैमसन ने 23 गेंदों पर 56 रन बनाकर भारत को मुकाबले में मजबूती से बनाए रखा, लेकिन ओपनिंग साझेदारी टूटने के बाद उस लय को बनाए रखना मुश्किल हो गया। आखिर में, जिससे वेस्टइंडीज को जीत मिली। भारत के लिए सबक यह है कि उन्हें अपना आक्रामक अंदाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके साथ बेहतर सूझबूझ दिखाने की जरूरत है। जब लक्ष्य का पीछा करते हुए प्रति ओवर 12 से अधिक रनों की जरूरत हो, तो बाउंड्री लगाना जरूरी है। लेकिन साथ ही, यह समझना भी जरूरी है कि कब एक सिंगल या दो रन लेकर स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया जा सकता है, ताकि दूसरे बल्लेबाज को अनावश्यक जोखिम में न डाला जाए। तिलक वर्मा के 43 और नीतीश कुमार रेड्डी के 41 रनों ने कुछ संघर्ष जरूर दिखाया।

अभिषेक कुमार सिंह

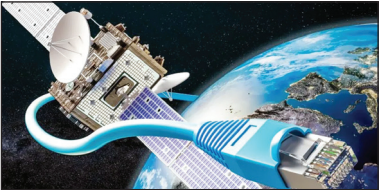
तकनीक के इस युग में युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़े जाते बल्कि डाटा, उपग्रहों और संचार नेटवर्कों के जरिये भी लड़े जाते हैं। ऐसे में, हाल ही में एलन मस्क और मुकेश अंबानी के बीच दिखाई दी प्रतिस्पर्धा को केवल दो उद्योगपतियों की कारोबारी लड़ाई मानना एक बड़ी भूल होगी। असली सवाल यह है कि भारत अपनी डिजिटल नियति का मालिक रहेगा या वैश्विक तकनीकी दिग्गजों के लिए केवल एक विशाल उपभोक्ता बाजार बनकर रह जाएगा? हाल ही में एलन मस्क ने भारत में स्टारलिनक की राह में कथित अवरोधों का संकेत दिया। उन्होंने इसके लिए अंबानी का नाम लेते हुए सोशल मीडिया पर टिप्पणी की।

पूछ कि क्या अंबानी भारत के असली बॉस हैं, तो बहस का केंद्र यह बना दिया गया कि कहीं भारत विदेशी निवेश को हतोत्साहित

तो नहीं कर रहा। लेकिन यह तर्क अधूरा है। किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र को यह अधिकार ही नहीं, बल्कि दायित्व भी है कि वह अपनी संचार व्यवस्था, डाटा सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों के अनुरूप नियम बनाए।

प्रश्न यह नहीं है कि स्टारलिनक भारतीय बाजार में आए या नहीं। प्रश्न यह है कि वह भारत की शर्तों पर आएगा या अपनी शर्तों पर। यहीं से बहस का वास्तविक स्वरूप शुरू होता है। ध्यान रखना होगा कि अब किसी भी देश के लिए इंटरनेट महज एक सुविधा नहीं, बल्कि सामरिक शक्ति है। एक दौर था जब दूरसंचार क्षेत्र का संबंध केवल फोन कॉल और प्रसारण सेवाओं से था।

आज इंटरनेट आर्थिक गतिविधियों, बैंकिंग, रक्षा, शासन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ बन चुका है। डिजिटल भुगतान से लेकर आपदा प्रबंधन तक सबकुछ नेटवर्क पर निर्भर है। ऐसे में उपग्रह आधारित



इंटरनेट सेवा किसी मोबाइल ऐप या ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसी सामान्य व्यावसायिक गतिविधि नहीं रह जाती।

ऐसे में, यदि किसी देश के करोड़ों नागरिकों का डाटा, संचार और डिजिटल जीवन एक विदेशी कंपनी के नियंत्रण वाले नेटवर्क पर निर्भर हो जाए, तो यह केवल व्यापार का नहीं, संप्रभुता का प्रश्न बन जाता है। यही कारण है कि दुनिया के हर बड़े देश ने डिजिटल अवसरंचना को रणनीतिक परिसंपत्ति माना है।

अमेरिका राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर प्रतिबंध लगाता है, यूरोप डाटा सार्वभौमिकता

को लेकर कठोर नियम लागू करता है। हमारा पड़ोसी देश चीन तो अपने डिजिटल ढांचे पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखता है और किसी भी विदेशी कंपनी को अपने यहां स्वतंत्र रूप से इंटरनेट संचालित करने की बूट नहीं देता है। फिर भारत यदि सुरक्षा और निगरानी संबंधी शर्तों पर जोर देता है तो उसे संरक्षणवाद क्यों कहा जाए?

इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत को लेकर पैदा की जा रही आपत्तियों का आधार यह है कि वह इस मामले में नियमों का सुचारु पालन चाहता है। उल्लेखनीय यह है कि भारत ने स्टारलिनक को नकारा नहीं है। सरकार ने लाइसेंस और निगरानी के लिए रास्ता खोला है। लेकिन भारत सरकार चाहती है कि भारतीय उपयोगकर्ताओं का डाटा, सुरक्षा प्रोटोकॉल और वैधानिक निगरानी भारतीय कानूनों के अनुरूप हो।

यही वह बिंदु है जहां अक्सर वैश्विक

तकनीकी कंपनियां असहज हो जाती हैं। उनका तर्क होता है कि इंटरनेट की प्रकृति वैश्विक है, इसलिए उस पर स्थानीय नियंत्रण सीमित होना चाहिए। लेकिन लोकतांत्रिक राश्यों का तर्क इससे भिन्न है। यदि कोई संकेत उत्पन्न हो, यदि साइबर हमला हो, यदि राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न खड़ा हो तो जवाबदेही किसी कंपनी के मुख्यालय की नहीं बल्कि सरकार की तय होती है।

इसलिए अंतिम अधिकार भी सरकार का होना चाहिए। भारत की मांग असाधारण नहीं है। असाधारण केवल यह अपेक्षा है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपने दरवाजे बिना किसी शर्त के खोल दे। इसलिए अब मामला अंबानी बनाम मस्क नहीं, बल्कि भारत बनाम निर्भरता का सवाल है। ताजा संदर्भों में सबसे बड़ी समस्या यह दिखाई देती है कि हर जटिल मुद्दे को व्यक्तियों की लड़ाई में बदल दिया जाता है।

150 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से स्थापित होगी इकाई, साढ़े तीन हजार से अधिक लोगों को मिलेगा प्रत्यक्ष रोजगार

उद्योगों को बढ़ावा देकर युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित कर रही सरकार : विष्णु देव

रायपुर। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास का लाभ प्रदेश के युवाओं तक रोजगार और आर्थिक अवसरों के रूप में पहुंचे, यह राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी उद्देश्य से नई औद्योगिक विकास नीति में ऐसे श्रम आधारित उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिनमें अपेक्षाकृत कम पूंजी निवेश के साथ बड़ी संख्या में रोजगार सृजित करने की क्षमता है। राज्य सरकार का लक्ष्य केवल निवेश आकर्षित करना नहीं, बल्कि निवेश को रोजगार, स्थानीय अर्थव्यवस्था की मजबूती और प्रदेश की समृद्धि का माध्यम बनाना है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज नवा रायपुर में यश फैन्स एंड एप्लायंसेस लिमिटेड की प्रस्तावित नई औद्योगिक इकाई के भूमिपूजन समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा

कि यश फैन्स एंड एप्लायंसेस लिमिटेड की नई इकाई छत्तीसगढ़ की औद्योगिक विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस परियोजना में 150 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्रस्तावित है और इससे साढ़े तीन हजार से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। इस इकाई में विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों के लिए उत्पादों का निर्माण किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन है। हमारी सरकार चाहती है कि छत्तीसगढ़ में ऐसे उद्योग अधिक से अधिक स्थापित हों, जो प्रदेश के युवाओं और महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराएं। जब युवाओं को अपने ही प्रदेश में कौशल और क्षमता के अनुरूप रोजगार मिलेगा तो उनके परिवार आर्थिक रूप से सशक्त होंगे



और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम के दौरान नवचयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि युवाओं के हाथ में नियुक्ति पत्र देना किसी भी औद्योगिक निवेश की सबसे सार्थक उपलब्धि है। एक रोजगार केवल एक व्यक्ति को आत्मनिर्भर नहीं बनाता, बल्कि पूरे परिवार के जीवन में आर्थिक सुरक्षा और नई उम्मीद लेकर आता है। मुख्यमंत्री ने युवाओं के लिए

बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर तैयार करने की पहल के लिए यश ग्रुप की सराहना की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत-2047 के संकल्प में छत्तीसगढ़ अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन, कौशल विकास और आधुनिक अधोसंरचना के विस्तार पर एक साथ काम किया जा रहा है।

प्रदेश में तीन हजार से अधिक उद्योग स्थापित

उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पिछले द्वाई वर्षों में प्रदेश में छोटे-बड़े मिलाकर तीन हजार से अधिक उद्योग स्थापित हुए हैं, जिनके माध्यम से 50 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। आगामी औद्योगिक परियोजनाओं से उड़ें लाख से अधिक लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होने की संभावना है। श्री देवांगन ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण और सरकार की निवेश हितैषी नीतियों के कारण निवेशकों का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत-2047 के संकल्प के अनुरूप विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए उद्योग, निवेश और रोजगार के क्षेत्र में निरंतर काम किया जा रहा है। उन्होंने यश ग्रुप की नई औद्योगिक इकाई को प्रदेश के औद्योगिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कंपनी प्रबंधन को बधाई दी। उन्होंने कहा कि परियोजना के समयबद्ध क्रियान्वहन के लिए राज्य सरकार द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री साय से एशियन गेम्स के कांस्य पदक विजेता एथलीट अनिमेष कुजूर ने की मुलाकात

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज शाम राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में एशियन गेम्स 2026 में कांस्य पदक जीतकर छत्तीसगढ़ और देश का गौरव बढ़ाने वाले एथलीट अनिमेष कुजूर ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय ने श्री कुजूर को उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई दी और उनके उज्ज्वल खेल भविष्य की कामना की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जशपुर की माटी के बेटे अनिमेष कुजूर ने अपनी प्रतिभा, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के बल पर अंतरराष्ट्रीय मंच पर शानदार प्रदर्शन कर पूरे छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित



किया है। एशियन गेम्स जैसे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय मंच पर पदक जीतना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। भारतीय टीम द्वारा राष्ट्रीय रिकॉर्ड में सुधार करना इस उपलब्धि को और विशेष बनाता है।

मुख्यमंत्री ने श्री कुजूर से एशियन गेम्स में उनके प्रदर्शन, प्रशिक्षण और खेल यात्रा के संबंध

में आत्मीय चर्चा की। उन्होंने कहा कि अनिमेष की उपलब्धि प्रदेश के उन हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो खेलों में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। छोटे से गांव से निकलकर अंतरराष्ट्रीय खेल मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करना यह साबित करता है कि प्रतिभा को उचित अवसर, प्रशिक्षण और प्रोत्साहन मिले तो हमारे युवा दुनिया के किसी भी मंच पर अपनी पहचान बना सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। बस्तर से सरगुजा और जशपुर तक हमारे जनजातीय और ग्रामीण अंचलों में अनेक प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं।

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में विश्व खाद्य दिवस का आयोजन

रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के अंतर्गत संचालित खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय में आज विश्व खाद्य दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में खाद्य सुरक्षा, पोषण, खाद्य प्रसंस्करण, खाद्यान्न की बर्बादी रोकने तथा खाद्य उद्योग में नवाचार एवं उद्यमिता को प्रोत्साहित करने



जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. एस.एस. सेंगर ने की।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने

कहा कि विश्व खाद्य दिवस हमें यह स्मरण कराता है कि पर्याप्त, सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन की उपलब्धता प्रत्येक व्यक्ति की बुनियादी आवश्यकता है। विश्वभर में खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा भुखमरी एवं कुपोषण जैसी चुनौतियों के समाधान के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। यह दिवस वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना की स्मृति में मनाया जाता है।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

विश्व एनेस्थीसिया दिवस पर पंचरक्षक अभियान



रायपुर। पं. जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर के एनेस्थीसियोलॉजी एवं पेन मेडिसिन विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. जया ललवानी के मार्गदर्शन में विश्व एनेस्थीसिया दिवस के अवसर पर जनजागरूकता एवं शैक्षणिक गतिविधियों की श्रृंखला आयोजित की गई। इस आयोजन में विभाग के संकाय सदस्यों डॉ. प्रतीक्षा अग्रवाल, डॉ. मंजुलता टंडन, डॉ. ए. शशांक, डॉ. अमृता जैन एवं डॉ. शाहिदा खातून ने सक्रिय सहभागिता एवं सहयोग प्रदान किया। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य आमजन को जीवनरक्षक कौशलों के प्रति जागरूक करना तथा सुरक्षित शल्य चिकित्सा में एनेस्थीसिया की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करना था। कार्यक्रम की पहली कड़ी में प्रातः 6:30 से 7:30 बजे तक रायपुर रेलवे स्टेशन पर पंचरक्षक अभियान के अंतर्गत जीवनरक्षक कौशलों का लाइव प्रदर्शन किया गया। विशेषज्ञों ने कार्डियोपल्मोनरी रिसिटेशन की तकनीक का प्रदर्शन किया। रेलवे स्टेशन पर उपस्थित यात्रियों एवं आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक हैंड्स-ऑन अभ्यास में भाग लिया।

सरकार दीपावली के पहले धान की खरीदी का अग्रिम भुगतान करे : कांग्रेस

रायपुर। सरकार द्वारा धान खरीदी दीपावली के पहले शुरू किये जाने की मांग कांग्रेस ने किया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि साल का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली सामने है यदि धान खरीदी दीपावली पर नहीं होगी तो किसान का हाथ खाली रहेगा ऐसे में त्योहार कैसे मनेगा? सरकार धान खरीदी दीपावली के पहले शुरू करे, यदि सरकार को धान खरीदी की तैयारी में दिक्कत है तो हर किसान के खाते में धान का अग्रिम राशि भुगतान किया जाए ताकि किसान दीपावली मना सके। जब धान खरीदी होगी तो उसमें यह राशि समायोजित की जाए। अमूमन दीपावली के समय कामगारों, कर्मचारियों को बोनस और अग्रिम देने की परंपरा है। यदि सरकार दीपावली के पहले धान नहीं खरीद सकता तो किसानों को अग्रिम राशि का भुगतान करे। धान खरीदी 1 नवंबर से शुरू किया जाना चाहिये। 1 नवंबर तक किसानों का धान खेतों से खलिहान में आकर बेचने के लिये तैयार हो जाता है। सरकार के द्वारा अभी तक धान खरीदी के लिए कोई तरीख घोषित नहीं किया है जिससे किसान चिंतित है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जब से राज्य बना है।

हाईकोर्ट ने जारी किया छुट्टियों का कैलेंडर

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वर्ष 2027 के लिए हॉलिडे कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें सालभर की छुट्टियों के साथ गर्मी और सर्दी के अवकाश की तारीखें भी घोषित की गई हैं। कैलेंडर में प्रमुख त्योहारों और राष्ट्रीय अवसरों पर मिलने वाली छुट्टियों की जानकारी दी गई है। इसके अलावा शनिवार और रविवार को हाईकोर्ट तथा रजिस्ट्री ऑफिस के खुलने और बंद रहने का शेड्यूल भी तय किया गया है। खास बात यह है कि कोर्ट की छुट्टियों के दौरान रजिस्ट्री ऑफिस अलग समय-सारणी के अनुसार काम करेगा। इससे वकीलों और पक्षकारों को पहले से तैयारी करने में मदद मिलेगी। जारी कैलेंडर के मुताबिक हाईकोर्ट में गर्मी की छुट्टी 18 मई से 11 जून 2027 तक रहेगी। इस अवधि में कोर्ट में नियमित सुनवाई नहीं होगी, लेकिन रजिस्ट्री ऑफिस खुला रहेगा। वहीं सर्दी की छुट्टी 23 दिसंबर से 31 दिसंबर 2027 तक निर्धारित की गई है। इस दौरान रजिस्ट्री ऑफिस 20 से 24 दिसंबर तक खुला रहेगा। इसके बाद 27 से 31 दिसंबर तक रजिस्ट्री ऑफिस बंद रहेगा। वर्ष 2027 में कई प्रमुख त्योहारों और राष्ट्रीय अवसरों पर छुट्टियां रहेगी। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 6 मार्च को महाशिवरात्रि, 10 मार्च को ईद-उल-फ़ितर और 26 मार्च को गुड फ्राइडे की छुट्टी रहेगी।

एसईसीएल मुख्यालय में अंतर-क्षेत्रीय हॉकी टूर्नामेंट 2026-27 का शुभारंभ

बिलासपुर । एसईसीएल मुख्यालय की मेजबानी में अंतर-क्षेत्रीय हॉकी टूर्नामेंट 2026-27 का स्व. बी.आर. यादव अंतराष्ट्रीय हॉकी मैदान, बहतलाई, बिलासपुर में शुभारंभ हुआ। इस प्रतियोगिता में एसईसीएल मुख्यालय सहित विभिन्न संचालन क्षेत्रों की कुल 16 टीमों भाग ले रही हैं। मुख्य अतिथि निदेशक (मानव संसाधन) बिरंची दास ने हॉकी मैदान पर गोल कर टूर्नामेंट का औपचारिक शुभारंभ किया। अपने संबोधन में श्री दास ने कहा कि हॉकी जैसे तेज गति के खेल में टीमवर्क, समन्वय और मानसिक दृढ़ता का विशेष महत्व है। खेल के मैदान में सीखे गए ये गुण कार्यस्थल पर भी सफलता प्राप्त करने में सहायक होते हैं। उन्होंने एसईसीएल में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने, बेहतर खेल सुविधाएं विकसित करने तथा खिलाड़ियों को बड़े मंचों तक पहुंचने के अवसर प्रदान करने पर जोर दिया। इस अवसर पर मुख्यालय के विभागाध्यक्ष, जेसीसी, कल्याण मण्डल, सिस्टा/एसोसिएशन के प्रतिनिधिगण, अधिकारी, कर्मचारी एवं डीएवीस्कूल प्रिंसिपल उपस्थित रहे।

81 प्रकरणों का मौके पर निराकरण



जशपुर। शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों की समस्याओं के त्वरित समाधान की दिशा में जशपुर जिले में महत्वपूर्ण पहल की गई है। जिले में लंबे समय से लंबित वेतन निर्धारण एवं पेंशन प्रकरणों के निराकरण के लिए आयोजित विशेष जिला स्तरीय शिविर में कुल 81 प्रकरणों का मौके पर ही समाधान किया गया। इनमें वेतन निर्धारण के 69 और पेंशन से संबंधित 12 प्रकरण शामिल हैं। इस पहल से सेवानिवृत्त हो चुके तथा सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच चुके शासकीय कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। कार्यालय सभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, अम्बिकापुर सभाग सरगुजा के निर्देशानुसार 14 अक्टूबर को कलेक्टरेट जशपुर के सभाकक्ष में विशेष शिविर आयोजित किया गया। शिविर में जिले के विभिन्न विभागों के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों ने अपने कार्यालयों से संबंधित लंबित वेतन निर्धारण एवं पेंशन प्रकरण प्रस्तुत किए। सभागीय अधिकारियों द्वारा इन प्रकरणों की दस्तावेजों सहित गहन जांच कर आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करते हुए मौके पर ही निराकरण किया गया।

प्रभारी सचिव ने विकास कार्यों और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की

जवाबदेही, टीम-वर्क और पारदर्शिता से तय होगी : सोनमणि

रायपुर। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव तथा दुर्ग जिले के प्रभारी सचिव श्री सोनमणि बोरा ने आज दुर्ग जिला मुख्यालय में अधिकारियों की बैठक लेकर विकास कार्यों और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बिजली, पानी, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता के साथ जिले में संचालित विकास योजनाओं, निर्माण कार्यों और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागों को पारदर्शिता, समयबद्धता, ईमानदारी और जवाबदेही के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।

प्रमुख सचिव श्री बोरा ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि जिले के समग्र विकास के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें, ताकि शासकीय



योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने प्रशासनिक कार्यों में आधुनिक तकनीक और उपकरणों का उपयोग बढ़ाने के साथ मानवीय संवेदनाओं एवं जनहित को सर्वोपरि रखने को कहा।

जिले के प्रभारी सचिव श्री बोरा ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने तथा पात्र हितग्राहियों को भूमि पट्टे एवं अन्य

आवश्यक दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा और बीबीजीआरवाई के अंतर्गत संचालित कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों में बालिकाओं के लिए शौचालय निर्माण सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता से पूरा करने को कहा। उन्होंने तहसीलों और ग्राम पंचायतों में

नामांतरण, बंटवारा तथा अन्य राजस्व प्रकरणों, विशेषकर एक वर्ष से लंबित मामलों का त्वरित और पारदर्शी निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला पंचायत और नगरीय निकायों के बीच समन्वय बढ़ाने तथा अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए स्टडी-टूर और क्रॉस-लर्निंग विजिट आयोजित करने के निर्देश दिए।

वन विभाग की समीक्षा के दौरान स्वामी आत्मानंद मॉडल कॉलेज, बोरी में पौधरोपण तथा तांदुला पार्क में नगर वन एवं हर्बल गार्डन की स्थापना जैसे नवाचारों की जानकारी दी गई। प्रभारी सचिव ने जिला शिक्षा अधिकारी को पीएमश्री सहित अन्य उत्कृष्ट विद्यालयों में साफ-सफाई, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, कचरा पेटी और उद्यान की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा आदिवासी संस्कृति को नष्ट करने पर तुली है। यूसीसी लागू करना पंचायत और नगरीय निकायों के बीच समन्वय बढ़ाने तथा अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए स्टडी-टूर और क्रॉस-लर्निंग विजिट आयोजित करने के निर्देश दिए।

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा सरकार में यूसीसी लागू करने जा रही है। यूसीसी से राज्य के 32 प्रतिशत आबादी आदिवासियों के हितों के खिलाफ है। यही कारण है कि सरगुजा से लेकर बस्तर तक आदिवासी समाज के लोग यूसीसी का विरोध कर रही है। यूसीसी



कमेटी सरगुजा गयी तो वहां पर लोग इसके खिलाफ में थे। बस्तर में भी आदिवासी समाज यूसीसी को लेकर चिंतित है। राज्य में आदिवासियों को विशेष संवैधानिक संरक्षण मिला है। प्रदेश में पेसा कानून लगा है। पांचवी अनुसूची भी है। आदिवासियों के लिए राजस्व संहिता में विशेष

प्रावधान है। विशेष संरक्षित जनजातियां भी है। यदि यूसीसी लागू हो गया तो इन अधिकारों का क्या होगा? सरकार स्पष्ट करे कि यूसीसी से आदिवासियों को नुकसान होगा की नहीं। छत्तीसगढ़ में यूसीसी की जरूरत क्यों है, भाजपा बताये?

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा सरकार अपने राजनैतिक एजेंडे को लागू करने जबरिया आदिवासियों पर यूसीसी थोप रही है, जिससे प्रदेश का आदिवासी समाज चिंतित है। राज्य में यूसीसी लागू होने पर आदिवासियों के हितों और अधिकारों का हनन बदाश्त नहीं किया जायेगा।

स्वीकृत निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में करें पूरा : कलेक्टर



वीवी जी रामजी के तहत स्कूलों में स्मार्ट टॉयलेट को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश

रायपुर। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने आज रेडक्रॉस सभाकक्ष में निर्माण एजेंसियों की बैठक लेकर स्वीकृत, प्रगतिरत एवं अप्रारंभ निर्माण कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने संबंधित विभागों एवं निर्माण एजेंसियों को सभी स्वीकृत कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए।

बैठक में कलेक्टर ने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (आरईएस), लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), शिक्षा विभाग, नगर निगम, जिला पंचायत सहित विभिन्न विभागों में पूर्व एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत निर्माण कार्यों की

प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कार्यों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करते हुए अप्रारंभ कार्यों को शीघ्र शुरू करने और प्रगतिरत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने समग्र शिक्षा के अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में बच्चों को अध्ययन के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना आवश्यक है।

कलेक्टर ने वीबी जी राम जी के तहत स्कूलों में स्वीकृत स्मार्ट टॉयलेट, दीवार निर्माण, फर्श निर्माण सहित अन्य छोटे-बड़े कार्यों को तत्काल पूर्ण किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि विद्यार्थियों को सुरक्षित एवं बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके।